1101
31/12/13

खण्ड : 6

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

संख्या : 9

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(षष्ठम् सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

वृहस्पतिवार, दिनांक : 4 जुलाई 1996 ई०

"शिक्षा, खेल और युवा सेवायें तथा कला और संस्कृति" के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिये, 22,89,31,75,250 (बाईस अरब, नवासी करोड़, ईकतीस लाख, पचहत्तर हजार, दो सौ पचास) रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री रामलाल सिंह कुछ कहते हुए सदन के वेल में आये।)

अध्यक्ष : हम इसके लिए टाइम देंगे । आप बैठिए। आपके प्रश्न को दूसरे माननीय सदस्य ने भी इस संबंध में मुझे कहा था। हम इस पर भी बोलवायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि हुई है। इस विषय पर अभी करवा दीजिये ।

अध्यक्ष : हमारी बात मान लीजिये। आप ही की बात नहीं है। सारे माननीय सदस्य, जो सब लोग हैं, बिजनेश ऐडवाईजरी कमिटी में बात तय हो गयी हैं इसको हम करवायेंगे । उनका जो प्रश्न है उस पर भी बहस करवायेंगे ।

कटौती पस्ताव : राज्य सरकार की शिक्षा, खेल और युवा सेवायें तथा कला और संस्कृति (स्वीकृत)

श्री प्रेम कुमार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक की मांग 10 रु० से घटायी जाये ।

हमारे दल की ओर से माननीय सदस्य श्री देवदयाल जी बोलेंगे ।

श्री चन्द्र मोहन प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हमारा भी एक प्रश्न है।

अध्यक्ष : हमने कह दिया कि कहीं से काटकर आपको समय दिया जायेगा ।

श्री शिवनाथ वर्मा : अध्यक्ष महोदय, डिवेट वाला पर क्या हुआ ?

अध्यक्ष : कल होगा। हम अभी घोषणा करेंगे ।

माननीय सदस्यगण., सभी दल के नेताओं को कहना चाहता हूं कि जो ये भावनात्मक मामला है। कल शून्यकाल में हम इसको रखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए । बजट में यह तय नहीं होगा।

श्री देव दयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार की सफलता और विफलता सदन में लम्बा-चौड़ा भाषण देने से पता नहीं चलता है। पता चलता है पूरे बिहार की जनता के बीच कि हम कितने सफल हुए हैं पता चलता है पूरे देश के लोगों के बीच कि बिहार में क्या हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसी से पता चलता है बिहार में जहां पहले पटना विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में दूसरे देश से विद्यार्थी, आकर पढ़ा करते थे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप माईक लेकर बोलिये ।

श्री देव दयाल : अध्यक्ष महोदय, मै चर्चा चला रहा था सफलता और विफलता पर । जिस बिहार में पहले दूसरे देश के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। आज बिहार में क्या हो गया ? यहां का विद्यार्थी यहां छोड़कर दूसरे प्रदेश में जाने के लिए बाध्य हो गये हैं और आपके भाषण में, वर्त्तमान सरकार के भाषण में 1990 से 1996 तक आपकी सरकार है, आपका क्या प्रोग्रेस है। इसका स्पष्ट कारण है कि भ्रष्टाचार सभी जगह फैला हुआ है जिसके चलते यहां आप हिम्मत भी नहीं करते है।

अध्यक्ष महोदय, भारी बदनामी हो रही है, बिहार में जहां भी जाते हैं, बिहार की बदनामी होती है कि बिहार के लड़के आये हैं। बिहार के विद्यार्थियों को दूसरी जगह एडमिशन नहीं हो रहा है। महोदय, मैं मूल बात पर आता हूं। आपके शासन में 1998 में साढ़े बारह अरब का बजट योजना मद में था और अभी आप दुगुना पर चले आये हैं, 23 अरब पर चले आये हैं विश्वविद्यालय खुला, नये विश्वविद्यालय का निर्माण किया लेकिन उसको आप अभी तक भवन नहीं दे पाये हैं मैं खासकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के बारे में कहना चाहता हूं, इस विश्वविद्यालय को एक करोड़ रुपया देने का वादा किया गया था, वह भी नहीं दिया गया। क्या सुविधा मिलेगा कैसे विश्वविद्यालय चलेगा । इसी तरह से कॉलेज के कर्मचारियों के बारे में चाहे वह शिक्षका का मामला हो या कर्मचारियों का मामला हो। सरकारी विभागों में जहां 124 प्रतिशत आप डी० ए० दे रहे हैं और विश्वविद्यालय में क्या

मिलता है 71 प्रतिशत । इतनी विषमता क्यों है ? आखिर क्या कारण है, बुद्धिजीवी जहां है, जंहा से विद्यार्थी कुछ हो करके बनते हैं, आगे बढ़ते है, तो इतनी विपमता क्यों रखे हुये हैं। मंत्री जी, मैं सुझाव के साथ अपना विचार भी दे रहा हूं, इस पर आप ध्यान दें । महाविद्यालय में जो लेक्चरर है, प्रोफेसर हैं, उनको आप प्रोन्नति नहीं दे रहे है। इसके संबंध में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी निदेश गया है, उसके बावजूद भी आप प्रोन्नति नहीं दे रहे है। आखिर ये लोग कैसे मन लगायेंगे पढ़ाने में, काम करने में ?

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात है वित्त रहित शिक्षा नीति के संबंध में । कॉलेजों और स्कूलों की बाढ़ हो गई है। जब आबादी बढ़ रही है तो आबादी के अनुसार आप क्या इसकी योजना नहीं बना सकते । नया विद्यालय, महाविद्यालय की स्थापना आप नहीं कर सकते है ? जहां खर्च होना चाहिये 100 रु० वहां खर्च हो रहा है 1000 रु०, आखिर आपके पास क्या योजना है, इस पर भी शिक्षा मंत्री का ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं । 32 विश्वविद्यालयों में भी० सी० एक नीति के तहत आना चाहिये। यह नहीं कि किसी के मर्जी से बैठा दिया जाय, इस तरह से किसी की नियुक्ति नहीं होनी चाहिये ।

महोदय, मैं इन्टरमीडिएट शिक्षा पर थोड़ी बात करना चाहता हूं। अभी 40 हजार विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग है, उनका क्या भविष्य होगा ? कैसे आगे पढ़ेंगे, वे दुविधा में है। आपकी क्या व्यवस्था हैं आपका ऑफिस आपके ऑफिसरान क्या कर रहे हैं कि 40 हजार विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग है। उसी तरह

इन्टरमीडएट कॉलेज के सचिव का अवैध नियुक्ति के मामले में कोर्ट से वारन्ट जारी हुआ है, भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है। चाहे बहाली में हो, चाहे पैसा खाने की बात हो या अन्य कोई भ्रष्टाचार की बात हो ।

, अध्यक्ष महोदय, अब मैं माध्यमिक शिक्षा पर थोड़ी बात करना चाहता हूं। मंत्री जी, इसमें भी 70 हजार विद्यार्थियों का भविष्य अंधेरे में है, रिजल्ट नहीं हुआ है, क्या व्यवस्था आपकी है, क्या कारण है कि आप शान्त बैठे हुये हैं क्या बिहर सरकार में लोग नहीं हैं । महोदय, किस तरह से विद्यार्थी को परेशान किया जाता है, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। नेतरहाट विद्यालय बिहार का टॉप विद्यालय है। यहां का एक विद्यार्थी 700 में से 526 नम्बर लाया और उसको भी फेल दिखलाया गया, यह देखकर उसका दिमाग खराब हो गया, क्या स्थिति हैं होनहार विद्यार्थियों का क्या भविष्य हो गया है, जो टॉपर्स हैं,उनको फेल दिखला दिया जाता है। उसी तरह से इन्दिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, हजारीबाग की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं । नेतरहाट के पेटर्न पर बच्चियों के लिये वह विद्यालय है लेकिन यहां की स्थिति यह है कि भवन की हालत जर्जर है, होस्टल की हालत जर्जर है, छत चूता है। कहां सोती हैं, कहां बैठती है लड़कियां, यह आपने कभी केयर किया है। इसके अलावे कई बार यहां के प्रिसिंपल और ऑफिसरों ने आपका ध्यान दिलाया लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। 1992-93 में नया स्कूल भवन बनाने के लिये पैसा दिया गया, मंजूरी दी गई। उस समय से 20 लाख रुपया फिक्स डिपोजिट में पड़ा

हुआ है और 9 लाख रुपया सिविल डिपोजिट में जमा है, कैसे विकास होगा। पूरे बिहार की बच्चियां उसमें पढ़ने आती है, उन बच्चियों के लिये कोई सुविधा नहीं है। वहां की व्यवस्था के बारे में आगे जानकारी देते हुए कहना चाहता हूं कि वहां जितने स्टाफ होने चाहिये, उतने नहीं है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया हैं । अध्यापिकाओं की स्वीकृत यूनिट 27 है, जिसमें मात्र 15 अध्यापिका हैं, 11 कम हैं तो वहां पढ़ाई की कैसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है ? एक डाक्टर की व्यवस्था है, डाक्टर नहीं है, एक प्रशासी की व्यवस्था है, वे भी नहीं गये हैं कर्मचारी वर्ग में 29 यूनिट है, जिसमें 23 है, 16 नहीं है। चतुर्थ वर्ग में 43 यूनिट है, जिसमें 10 हैं इस तरह से व्यवस्था के बीच क्या पढ़ाई होगी वैसे विद्यालयों में ।

महोदय, अब मैं सरकारी जिला स्कूलों के बारे में बताना चाहता हूं । खासकर हजारीबाग के जिला स्कूल को देखेंगे तो पता चलेगा कि यह पहले का यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है, उसकी हालत भी जर्जर है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। उसका किवाड़, चौखट, छत जर्जर हो रहा है। मैंने सरकार से आग्रह किया, लिखित दिया, क्वेश्चन भी दिया लेकिन उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि आप नया 10 भवन बना देंगे और यदि मरम्मति करेंगे तो ज्यादा सफलता होगी। हजारीबाग जिला स्कूल बालिका का होस्टल 10 वर्षो से निर्माण कार्य शुरू हुआ और तैयार हो गया हैं । मात्र किवाड़, चौखट लगाना बाकी है, खिड़की भी अभी नहीं लगी है, उसमें गरीब, हरिजन-आदिवासी के बच्चे रहते हैं, उनके

लिये यह होस्टल है लेकिन यह सब नहीं किया जा रहा हैं । एक तरफ प्रशिक्षण विद्यालय, महाविद्यालय बन्द कर उसके स्टाफ और शिक्षकों को बैठा करके रखे हुये हैं और दूसरी तरफ स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षक नहीं है। इनसे आप काम नहीं लेते हैं। जिस समय वे प्रशिंक्षण में जायेंगे, उस समय प्रशिक्षण लेंगे, अभी इन लोगों से काम लेना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मेरा एक सुझाव है कि आप माध्यमिक शिक्षा को एक जगह सेंट्रलाईज किये हुये हैं, इसका एक ब्रांच रांची में भी होना चाहिये ताकि लोगों को सुविधा होगा रिजल्ट निकालने में और प्रशासनिक दृष्टि से भी। इसी तरह से वित्त रहित माध्यमिक शिक्षा के लिये आप मंजूर देते हैं लेकिन जो शर्त्त पूरा करते हैं, उनको भी नहीं देते हैं जिसके कारण विद्यार्थी फार्म भरने दूसरे विद्यालय में जाता है तो उसको 100-200 के जगह एक हजार देना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय, एक अहम बात और कहना चाहता हूं । आप 10 वर्षों से पदस्थापित शिक्षकों की बदली कर रहे हैं, चाहे प्राथमिक के हों या उच्च विद्यालय के हों लेकिन यह बदली प्रशासनिक दृष्टि से नहीं, विकास की दृष्टि से नहीं की जा रही है। आर० डी० ए० का दो-दो लाख रुपया लेकर ट्रांसफर किया जा रहा है और वैसे आर० डी० डी० को बैठाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों कीबदली में मनमाने ढंग से दस-दस हजार, पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपया किया जाता है और उनके इच्छानुसार उनकी बदली की जाती है। आखिर ऐसा क्यों ?

(इस अवसर पर पीठासीन पदाधिकारी श्री राजो सिंह ने आसन ग्रहण किया।)

(व्यवधान)

आप सुनने के लिये धैर्य रखिये। यदि हम गलत बात कह रहे हों। आप धैर्य से सुनिये ।....

(इस अंश को सभापति महोदय के आदेश से विलोपित किया गया है।)

हजारीबाग के आर० डी० ए० का अभी डेढ़ साल भी नहीं हुआ था तो क्या तुक था कि वहां से आप बदली कर दिये। जबकि वे हरिजन हैं, क्या तुक है? जिन शिक्षकों से दस-दस हजार रुपया लिया गया है। हम जानते हैं, उनसे लिया गया है और मनचाहा जगह पोस्टिंग किया गया है। आखिर इस तरह की व्यवस्था क्यों ? एक नीति के तहत जिनको जहां भेजना है, वहां भेजिए। हम यह नहीं कहते हैं कि दो लाख रुपया कौन लिए । आप इसकी छानबीन तो कराइए। जो प्रभावित शिक्षक हैं, उनसे आप पूछिए। आप शासन में बैठे हुए है। आप की सरकार है, अभी आप राजा है। कुछ गरीब शिक्षकों के बारे में सोचिए। उसी तरह से जिला शिक्षा अधीक्षक पांच हजार-सात हजार रुपया लिया करते है।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, मेरा प्वांट ऑफ औंर्डर हैं विपक्ष के एक सदस्य बोल रहे है। लेकिन जो सच्ची बात है, नियमतः बातें है, इस सदन में होती रही है। वह

सदन में आनी चाहिये। जो बातें उन्होंने कही है, नियमतः इतना बड़ा इलिगेसन, घूस लेने का लगा दिया, अनलेस कोई कागजात नहीं है, तब तक यह बात गैरइंसाफी है। व्यक्तिगत भी और सदन के साथ भी, इसलिए इसको आप स्पंज कर दीजिये ।

सभापति : इसको हटा दिया जाय। जो डायरेक्ट आरोप लगाया गया है; उसको प्रोसीडिंग से हटा दिया जाय ।

(व्यवधान)

आप बैठ जाइए। समय इनका नस्ट हो जायेगा। महेन्द्र बाबू जब आपका समय आयेगा तो बोलियेगा। सही बात आनी चाहिए। अगर रामाश्रय बाबू से सही बात कह दिया तो कोई अन्याय नहीं हुआ।

श्री देव दयाल : सभापति महोदय, इसकी जांच तो कराइए। जो शिक्षक सकूल नहीं जाते हैं, वे अफसर को महीना, दो-चार सौ रुपया बांध दिये हैं। वे कहां से पढ़ाई करेंगे । हमारे क्षेत्र में, नगर स्थित का एक उदाहरण दे रहा हूं। पतरातु गांव में 6 शिक्षक थे और मैं गया उस स्कूल को देखने के लिए तो उस स्कूल में कोई भी शिक्षक नहीं थे। कोई शिक्षक स्कूल में आता ही नहीं हैं। आप इसकी जांच कराइये । इसी तरह से एक विद्यालय हमारे क्षेत्र में है और वहां पर तीन वर्षो में मात्र तीन ...

(व्यवधान)

श्री लाल बाबू प्रसाद : सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर हैं मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर यह है कि...

(इस अंश को सभापति महोदय के आदेश सें विलोपित किया गया है।)

श्री देव दयाल : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के एक प्रखंड में एक बालिका प्रोजेक्ट विद्यालय है। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं। तीन वर्षो में मात्र तीन लड़कियां ही माध्यमिक शिक्षा में पास हुई और इस संबंध में जब मैंने शिकायत किया कमिश्नर के यहां तो कहते हैं कि प्रधानाध्यापिका को सस्पेंड करेंगे । लेकिन महोदय वहां कोई शिक्षक नहीं जाते हैं और न पढ़ाई ही होती है। शिक्षक लोग सिर्फ वेतन उठाते है। इसको आप गंभीरता से लें। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

प्रतिनिधि के नाते कह रहे है। अगर प्रतिनिधि पर अंगुली उठाना है तो उठा सकते है।

श्रीमती सीता सिन्हा : सभापति महोदय,...

सभापति : आपका भी नाम है। बोलने के समय बोलियेगा। आप नोट करके रखिए।

श्री देव दयाल : सभापति महोदय, 64,294 प्राथमिक विद्यालय हैं और शिक्षक 14 हजार कम है। अभी भी 14 हजार शिक्षकों की कमी है। कैसे पढ़ाई होगी पूरे बिहार में। उसी तरह सें हजारीबाग नगर क्षेत्र में, मैं अपनी क्षेत्र की बात कहता हूं भवन की बात कह रहा हूं। 64 हजार 294 विद्यालय हैं जिसमें से 8 हजार 944 विद्यालय में भवन नहीं है। हमारे क्षेत्र के

हजारीबाग नगर में 25 प्राथमिक विद्यालयों में भवन ही नहीं है। क्या पढ़ाई होगी ।

सभापति : आपके रहते विद्यालय भवन नहीं है।

श्री देव दयाल : हम तो सरकार से मिलते ही रहते है। सरकार के सामने आवाज उठाते ही रहते हैं । हमारे जो प्रेस भाई है, वे वहां तक आवाज पहुंचा देते है। लेकिन जनता कहती है कि विधायक जी तो बहुत बोलें, लेकिन सरकार से क्या मिला, कछ नहीं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे नगर क्षेत्र में जो 25 विद्यालय में भवन नहीं है, उसका आप भवन बना दीजिए । उसी तरह से प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नहीं आते हैं, उन्होंने तो अफसरों को माहवारी बांध दिया है, जिसके कारण शिक्षक लोग स्कूल नहीं जाते हैं । इसलिए मंत्री जी, इसकी आप जांच कराइए। डी० एम० सी० और इनके एरिया अफसरों की मिलीभगत रहती है। इसकी भी आप जांच कराइए। आप खुला जांच करायें, इसके लिए हम भी तैयार हैं बच्चों के लिए रूटिन है, सिलेब्स है। आज की पढ़ाई आज होनी चाहिए। मैं 17 वर्षो तक विद्यालय में शिक्षक का काम किया सरकारी विद्यालय में। इसलिए मुझे इसका अनुभव है। इसलिए आज की पढ़ाई आज होनी चाहिए। मेरा निवेदन है कि इसको आप कीजिए । तीन हजार, चार हजार, पांच हजार रुपया वेतन दे रहे हैं शिक्षकों को और वे पढ़ाते नहीं है। आखिर इसके देख-रेख के लिए इतने पदाधिकारी क्यों हैं? डायरेक्टर तक पदाधिकारी हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूं कि बहुत-से ऐसे जगह हैं, देहातों में, जंगल में जहां प्राथमिक विद्यालय हैं, लेकिन माध्यमिक विद्यालय नहीं हैं इसलिए इसको उत्क्रमित कीजिए। हरिजन-आदिवासी जो दूर-दराज दस-दस किलोमीटर, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर तक दूसरी जगह पढ़ने के लिए आते हैं, एक चौथाई से जाते हैं और तीन चौथाई नहीं जाते है। इसलिए इसको उत्क्रमित कीजिए । बहुत खुशी की बात है कि कल मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम 500 की आबादी पर एक विद्यालय खोलने जा रहे है। चाहे टोला हो या गांव हो, जहां विद्यालय नहीं खोले गये है। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं...

(व्यवधान)

300 पर कर रहे है। बहुत खुशी की बात है।

सभापति : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री देव दयाल : सभापति महोदय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष तीन महीने से अपने कार्यालय कक्ष में नहीं जाते है।, मुलाकात करने से भी कतराते है। सभापति महोदय, जिला शिक्षा अधीक्षक, रोहतास, श्री हाशमी जिनका तबादला छः माह पूर्व आरा में कर दिया गया था, इनके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा भी है और न्यायालय ने इन पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

सभापति : माननीय सदस्य श्री देव दयाल जी, आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठिये ।

श्री देव दयाल : सभापति महोदय, आपका आदेश है तो हम बैठेंगे ही लेकिन शिक्षा, पानी और भोजन देना सरकार का काम है।

सभापति : भोजन भी ?

श्री देव दयाल : हां। चावल घटेगा तो व्यवस्था नहीं करेंगे ? पानी घटेगा तो पानी नहीं देंगे ?

सभापति : ठीक है, ठीक है। अब आपका भाषण समाप्त हुआ, आप बैठिये । श्री रवीन्द्र चरण यादव जी, अपना भाषण शुरू करें ।

श्री रवीन्द्र चरण यादव : सभापति महोदय, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

श्री देव दयाल : सभापति महोदय, मुझे एक बात कहने के लिए मौका दिया जाय। राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों को 10- माह से वेतन और अन्य सुविधायें नहीं मिल रही है, उनको वेतन मिलना चाहिए।

सभापति : ठीक है, ठीक है । अब आप बैठिए । माननीय सदस्य, श्री रवीन्द्र चरण यादव जी ।

श्री रवीन्द्र चरण यादव : सभापति महोदय, मैं मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मानव संसाधन विकास विभाग का बजट है, माननीय सदस्य, हमारे साथी देव दयाल जी, अपनी बात कह रहे थे शिक्षा विभाग के बारे में । महोदय,

'हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं,
सूरत बदलनी चाहिए, आग जरूर है कहीं,
मेरे दिल में न सही, तुम्हारे दिल में ही सही,
परिवर्त्तनकारी इनकलाब की आग जलनी चाहिए ।'

सभापति महोदय, साथी देव दयाल जी बात कर रहे थे, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सदस्य बोल रहे थे। सरकार की क्या उपलब्धि है, सरकार क्या करना चाहती है, मैं संक्षिप्त शब्दों में अपनी बातों को रखूंगा लेकिन साथ-ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, महोदय, एक बार हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक व्यक्ति ने हजरत साहब पर एक पत्थर फेंका और कहा कि यह कौम का सबसे बड़ा गुनहगार है, इस पर हजरत साहब ने कहा कि शुक्रिया आगे बढ़ने पर एक दूसरे व्यक्ति ने हजरत साहब पर रोड़ा फेंका और कहा कि यह सबसे बड़ा जालिम और दुष्ट है, इस पर भी हजरत साहब ने उस व्यक्ति को शुक्रिया कहा । महोदय, हजरत साहब के साथ जो चेला लोग थे, उनलोगों ने हजरत साहब से कहा कि जो आपको गुनहगार और काफीर कह रहा है और आप पर पत्थर फेंक रहा है, उसकी आप शुक्रिया कर रहे हैं ? हजरत साहब ने कहा कि दोष उनका नहीं है बल्कि दोष उनके संस्कार का हैं जिसका जैसा आईना, तस्वीर लगे उनकी वैसी । इसलिए जो संस्कार इनका है, जो चरित्र है, रूढ़िवादी, कट्टरवादी, पाखंडवादी, यथार्थवादी व्यवस्था में ये विश्वास करते हैं तो इनको वैसी ही तस्वीर नजर आती है। महोदय, हमको इसमें कोई खंडन नहीं करना है।

सभापति महोदय, शिक्षा बदलते हुए युग और ले रही समय की अंगराईयों के बीच राष्ट्र की एकता और अखण्डता को मजबूत करती है, शिक्षा संस्कार बदलती है, शिक्षा संस्कार को नया आयाम देती है, शिक्षा युग को नई दिशा और दृष्टि प्रदान करती है, शिक्षा समाज का प्रतिबिम्ब बनती है, शिक्षा मानव की सभ्यता और संस्कृति का दीपक होता है, शिक्षा मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, शिक्षा मानव संस्कार के अतीत की गौरवमयी आयाम को सुदृढ़ करती है। लेकिन महोदय, पांच हजार वर्षो में जो शिक्षा की व्यवस्था रही है, मनुवादी, रूढ़िवादी, पाखंडवादी, यथार्थवादी, भोगवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी, जो घृणा-नफरत पर आधारित, उपहास और शोषण पर आधारित शिक्षा व्यवस्था रही है उस व्यवस्था को तोड़कर समता और समानतावादी, बराबरी, रोजगारोन्मुखी व्यवहारिक शिक्षा देना जनता दल और लालू प्रसाद याद्व जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है।

सभापति महोदय, सरकार ने विगत 5 वर्षो में, पहले शिक्षा माफिया के ट्रेनिंग पास किये हुये लोगों की नियुक्ति होती थी लेकिन पहली बार क्रीम को निकालकर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से 25 हजार शिक्षकों को नियुक्ति करने का काम किया, चार हजार हाई-स्कूलों में टीचर की बहाली की गई और 4 हजार लेक्चरर की बहाली के लिए पात्रता हुई है, फिर उसके बाद की परीक्षा हो रही है।

सभापति महोदय, इस सरकार ने चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया है। मैं मानता हूं कि चरवाहा विद्यालय में हो

सकता है कहीं भोजन और कपड़ा नहीं दिया जाता है, मुझे पूरे बिहार का अनुभव नहीं है लेकिन जहां कहीं है मैं अपने क्षेत्र की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, मैं आपको न्यौता देता हूं, आप चलकर देखिए, चरवाहा विद्यालय में वहां शिक्षा व्यवस्था है, भोजन दिया जाता है, पढाई दी जाती हैं आपलोग चरवाहा विद्यालय का उपहास करते हैं महोदय, भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता का दर्शन दिया, वे गाय चराया करते थे, गाय चराने वाले कृष्ण ने गीता का दर्शन दिया, हजरत मोहम्मद साहब जो भेड़ चराते थे, जिन्होंने कुरान का दर्शन दिया और उसी तरह से ईसा-मसीह भी भेड़ चराया करते थे जिन्होंने बाईबिल का दर्शन दिया। सभापति महोदय, मंदिर में पाप करने वाले ही सिर्फ सभ्यता और संस्कृति का दर्शन दे सकते हैं बल्कि चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाला भी अब शिक्षा और संस्कृति का दर्शन दे सकते है बल्कि चरवाहा विद्यालय में पढ़ने वाला भी अब शिक्षा और संस्कृति की शिक्षा देगा। इसलिए चरवाहा विद्यालय खोलकर हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने गरीबों को सम्मानित करने का काम किया है। महोदय, आज चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग में कम-से-कम जिला शिक्षा योजना समिति का गठन किया गया हैं । जिला शिक्षा योजना समिति के माध्यम से सभी माननीय विधायकों को

उसका सदस्य बनाया गया है। जिला शिक्षा योजना समिति का काम है प्राईमरी स्कूल नया खोलना, प्राईमरी स्कूलों को अपग्रेड करना, नये यूनिट को सैंक्शन करना। माननीय मंत्री ने सभी विधायकों को उस समिति का सदस्य बनाया हैं सभापति महोदय, हरिजन-आदिवासी लोगों को जो 40 वर्षों से नियुक्ति में जो बैकलौग था, उस बैकलौग को पूरा करने का काम इस सामाजिक न्याय की सरकार, माननीय लालू प्रसाद यादव जी की जनता दल की सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, हाई-स्कूलों में प्रबंध समिति का गठन किया गया हैं और उस प्रबंध समिति के माध्यम से काम होगा। हाई स्कूलों में जो 30-40 वर्षो से शिक्षक पदस्थापित थे, उन टीचरों का ट्रांसफर करके मेधावी टीचर, मूर्धन्य, विद्वान और सामाजिक न्याय के लोगों को सही ढंग से पदस्थापित किया गया है। सभापति महोदय, इस सरकार ने नये विश्वविद्यालय खोलने का काम किया है, आज सरकार ने मण्डल विश्वविद्यालय, सिंधू-कानू विश्वविद्यालय, बिनोबा भावे विश्वविद्यालय, बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना की है। सभापति महोदय, सरकार ने विद्यालयों में एकेडमिक काउंसिल की स्थापना की है।

श्री जवाहीर प्रसाद : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री रवीन्द्र चरण यादव जी कह रहे थे कि कृष्ण भगवान गईया चराते थे लेकिन आज बिहार में गईया की क्या स्थिति है ? यह वे बतावें । यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति : यही व्यवस्था का प्रश्न है आपका ? इतना सीरियस टॉक हो रहा है।

श्री रवीन्द्र चरण यादव : सभापति महोदय, सरकार ने विश्वविद्यालयों में एकेडमिक कैलेन्डर की घोषणा की है, सीनेट और सिंडिकेट का गठन किया है, जो विगत वर्षों में नहीं किया गया था। सभापति महोदय, बिहार की 9 करोड़ जनता की आकांक्षाओं का यह सदन हैं महोदय, सम्पूर्ण निजाम बदल गया, शिक्षा का आयाम बदल गया, मंजिल तक हम पहुंचकर मंजिल के आसपास मंजिल को खोजते हैं, किनारे तक पहुंचने के लिए किश्तियां साहील को खोजती हैं तो महोदय, पूरी व्यवस्था को बदलना होगा।

सभापति महोदय, अरस्तु ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन वहां कर सकते हैं जिसके लिए व्यवस्था परिवर्तन करना जरूरी हैं जिसकी व्यवस्था है, वह व्यवस्था परिवर्त्तन नहीं होने देगा। इसलिए उनकी रणनीति और पाखण्ड को बदल कर कुचल कर करेंगे ।

सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कुछ राय देना चाहता हूं ।

आज प्राईमरी स्कूल और मध्य विद्यालय में जो गड़बड़ियां हैं जहां हेडमास्टर को ड्राइंग और डिसबर्सिंग पावर है, उनके द्वारा 90 के पहले के टीचरों को भुगतान किया जा रहा हैं आप मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के ड्राईंग और डिसबर्सिंग पावर को खत्म कीजिए । किसी विद्यालय में 14 टीचर हैं और किसी विद्यालय में दो टीचर हैं इसमें समानता लानी चाहिए और हमारे

मुसलमान भाईयों का जो प्राईमरी, मिडल और हाई सकूल है, उसमें उर्दू टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन होगा कि सरकार इस पर गंभीरता से निर्णय ले।

बहुत से हाई स्कूल और बेसिक स्कूल में किसी में 10 एकड़ किसी में 20 एकड़ किसी में 50 एकड़ जमीन पड़ा हुआ हैं वैसे खाली पड़े जमीनों से स्कूल का विकास किया जा सकता है।

हमारे माननीय सदस्यों को चिंता रहती है कि स्कूल भवन निर्माण के लिए योजना मद में एक पैसा नहीं है। सरकार कहती है कि डी० आर० डी० ए० से बनवा देंगे लेकिन इसके लिए शिक्षा मंत्री महोदय, ग्रामीण मंत्री महोदय और ग्रामीण सचिव की राय ले लें, एक संकल्प करा लें कि डी० आर० डी० ए०, सघन रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना की कितनी राशि व्यय की जाए और एक साल के अंदर सभी विद्यालय का पक्का भवन बन जाए।

सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों में वर्ष 1985-86 से पद खाली है। पटना विश्वविद्यालय में हमारे विरोधी दल के नेता प्रश्न उठाते रहते थे। मैं भी वहां सेंडीकेट का मेम्बर था। वर्ष 1985 से पटना विश्वविद्यालय का अंकेक्षण नहीं हुआ है। ऑर्डिटर लोग टी० ए०, डी० ए० लेते रहते है। मैने सेंडीकेट को सस्पेंड करवाया था। आपसे अनुरोध है कि उनका ऑडिट अप-टू-डेट कराया जाए ।

सभापति : अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रवीन्द्र चरण यादव : सभापति महोदय, एक मिनट। विश्वविद्यालय में क्राईटेरिया बनवाइये। वहां रजिस्ट्रार, फाईनेन्स ऑफिसर, बजट ऑफिसर का पद खाली है। उस पर बहाली की जाय।

सभापति महोदय, सरस्वती शिशु मंदिर एक आर० एस० एस० का स्कूल है। गार्जियन से एक हजार रुपया लेकर एडमीशन करते है। एक बनवासी कल्याण केंन्द्र विद्यालय छोटानागपुर में है जिसे भारत सरकार द्वारा अनुदान मिलता है। इन दोनों विद्यालयों की जांच करायी जाय।

सभापति : आप माननीय सदस्यों से एक इजाजत चाहता हूं। आज शिक्षा विभाग पर बहस चल रही है। मैं चाहता हूं कि दो विरोधी दल से और एक रूलिंग पार्टी से बोलिए। इस संबंध में आपसे राय लेता हूं। विरोधी दल के लोगों को बात कहने दें आपका तो चिट्‌टी-पत्री से भी काम चल जाता है।

(रूलिंग पार्टी के माननीय सदस्यों ने सहमति प्रकट की।)

श्री राधा कृष्ण किशोर : सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष की ओर से दिए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोल रहा हूं।

आज संपूर्ण सदन वर्ष 1996-97 के लिए शिक्षा बजट पर विचार कर रहा है। ऐसे परंपरा रही है कि सरकारी पक्ष के लोग सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें और प्रतिपक्ष के लोग उनकी खामियों को उजागर करे, लेकिन शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर जब सदन में चर्चा हो रही है तो हमारा

और आपका फर्ज बनता है कि जो वास्तविक स्थिति है, उसकी चर्चा करें ।

सभापति महोदय, जिन बातों को मैं यहां कहना चाह रहा था, मैने देखा है पूरे हिन्दुस्तान में, जो शिक्षा की स्थिति हमारे प्रदेश में है वह कहीं नहीं है। मैंने पिछले वर्ष मानसून सत्र में इस बात का उल्लेख भी किया था। पूरे हिन्दुस्तान में, दूसरे राज्यों की तुलना में हमारे यहां साक्षरता का प्रतिशत काफी कम है। मैं उसकी चर्चा, पुनरावृति नहीं करना चाहता हूं लेकिन सभापति महोदय, आप स्वयं ही एक शिक्षित और अनुभवी व्यक्ति है। आपको पता होगा कि बिहार में, जब यहां नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसके बारे में मैने पढ़ा है कि ह्वेसांग ने कहा है कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र था और उस समय राजकोष से नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर खर्च किया जाता था। उस समय दस हजार विद्यार्थी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। एशिया और दूसरे कई देशों से विद्यार्थी वहां पढ़ने आते थे और आज बिहार प्रदेश के बच्चे अच्छी पढ़ाई के लिए बिहार को छोड़कर दूसरे प्रांत में जा रहे है। आज यहां की पढ़ाई की व्यवस्था पर उन्हें विश्वास नहीं रह गया है, यहां के शिक्षा के स्तर पर विश्वास नहीं रह गया है। आपके अभिभावक, हमारे अभिभावक अपने बच्चों को दूसरे प्रदेश में भेजते हैं। एक वह समय था जब दूसरे देशों के लोग यहां आते थे, उस समय के छात्र को जब तक नालंदा विश्वविद्यालय की उपाधि नहीं मिल जाती थी, उनकी पढ़ाई अधूरी मानी जाती

थी। आज दूसरे प्रदेश में बिहार के किसी भी शैक्षणिक संस्थानों की उपाधि की मान्यता को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। यह बहुत खुशी की बात है कि आपने कदाचार मुक्त परीक्षाएं कराई, इसमें हमारा कोई दूसरा मत नहीं है लेकिन माननीय मंत्री जी, इस बात को आप भी मानेंगे कि जो कदाचार मुक्त परीक्षा के बाद जो परीक्षाफल का प्रतिशत आया है, 6 प्रतिशत, 12 प्रतिशत उसको देखने से पता चलता है जिस रूप से पढ़ाई आपके शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाई होनी चाहिए थी वह नहीं हुई थी और कदाचार मुक्ति के आधार पर भले हमारा काम अच्छा हो जाये, जिस दिन कदाचार के नाम पर नियंत्रण किया गया, उसका प्रतिशत घट गया। ऐसा क्यों हुआ ? कहीं पढ़ाई नहीं हुई, शिक्षक पढ़ाई नहीं किए। यह बहुत गंभीर बात है ।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा के बारे में यह चर्चा करना चाहता हूं कि बिहार में जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि यह बात सिर्फ छः वर्षो में नहीं हुई है लेकिन आज शिक्षा के स्तर में जो गिरावट हुई है, जो स्तर बना है, बिहार में उनके लिए एक कारण यह भी है कि आज बिहार में सात हजार सात सौ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भवन नहीं हैं छोटानगपुर क्षेत्र में 40 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय तक नहीं है और माध्यमिक विद्यालयों में जो समस्या बन गयी है कि कोई शिक्षक वहां जाते नहीं है। यह आंकड़ा बताता है कि आपके प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए जहां 2,25,296 पद सृजित हैं वहां 19 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं जहां आपके राज्य में 19 हजार शिक्षकों

की बहाली नहीं हुई है, वैसे स्कूल जहां शिक्षक नहीं जाते है, पद सृजित नहीं होता, वहां आप कल्पना कीजिए कि क्या होगा। मैं शिक्षा व्यवस्था के संबंध में यह बताना चाहूंगा कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सरकार को जो राशि खर्च करनी चाहिए वह नहीं करती है। जहां दूसरे राज्यों में शिक्षा के वार्षिक बजट पर 30-40 प्रतिशत खर्च होता है, यहां नहीं होता है।

सभापति महोदय, बिहार का जो वार्षिक बजट है वह एक खरब रुपया है और आपका जो शिक्षा पर बजट है वह 22 अरब रुपया है मैं आंकड़ा में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जहां आन्ध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में जो वार्षिक बजट है शिक्षा पर वह आपके प्रदेश, राज्य के अपेक्षा कहीं ज्यादा है। हुआनसांग ने कहा था कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र इतने अच्छे क्यों होते थे इसलिए होते थे कि राजकोष से उनके पढ़ाई की मुफ्त व्यवस्था की जाती थी, उनके बिस्तर, उनके भोजन, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए शिक्षा उपलब्ध करायी जाती थी यानि यह प्रमाणित करता है कि उस समय शिक्षा पर ज्यादा खर्च किया जाता था।

सभापति : माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर जी अब आप अपना भाषण समाप्त कीजियें ।

श्री राधा कृष्ण किशोर : सभापति महोदय, अभी मैंने शुरू ही किया है। सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर शिक्षा के स्तर में, शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना चाहते हैं तो आपको अधिक राशि शिक्षा पर खर्च करना होगा। उच्च

शिक्षा की बात करते है। क्या आपको सेंट्रल असिस्टेंट मिलता है ? दूसरे राज्यों की अपेक्षा वह काटकर मिलता है। आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 95-96 में 920.59 लाख रुपया दिया गया केन्द्र के द्वारा, आसाम में जहां 254.35 लाख रुपया दिया गया केन्द्र के द्वारा वहीं बिहार को 269.58 लाख रुपया दिया गया। क्यों आपको केन्द्र के द्वारा यह अनुदान नहीं मिलता है ? इसलिए नहीं मिलता है कि राज्य सरकार को अपने अंश का, अपने हिस्सा का जो राशि वहां देना चाहिए आप वह राशि नहीं जुटा पाते है इसलिए आपको केन्द्र द्वारा अनुदान नहीं मिलता है।

सभापति : माननीय सदस्य, श्री राधा कृष्ण किशोर जी अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, ये अच्छा बोल रहे हैं। इनको बोलने दिया जाये।

सभापति : 5 बजे तक का समय है। लिस्ट में बहुत से माननीय सदस्यों का नाम है।

श्री राधा कृष्ण किशोर : सभापति महोदय, मैं शिक्षा के मामले में इन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता कि पांच हजार लेकर शिक्षकों का पदस्थान होता है या 10 हजार लेकर होता है। यह मूल विषय नहीं है मूल विषय यह है कि आपका कंसेप्ट क्या है, बिहार में शिक्षा को मजबूत करने लिए आपकी इच्छा शक्ति क्या है, प्रतिबद्धता क्या है ? मैं इन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि आपके स्कूल भवनहीन हैं मूल कारणों को बताना चाहता हूं कि आप पैसा खर्च कीजिए। आपके यहां

केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रतीक था शिक्षा जगत में, पूरे विश्व में इसका नाम था। बिहार की धरती में अभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैं । शिक्षा के जगत में इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है ?

सभापति : मनुष्य की परिस्थति, हुआनसांग का जो जमाना था उस समय ताला नहीं लगता था और कागज का नोट नहीं चलता था, वह रुपया सोना का होता था।

श्री राधा कृष्ण किशोर : सभापति महोदय, मनुष्य की और सरकार की अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो तो वह खराब परिस्थिति को भी अच्छा परिस्थिति में बदल सकता है।

सभापति : इच्छा शक्ति से कुछ होने वाला नहीं है। अब आप बैठ जाइये। माननीय सदस्य, श्री त्रिवेणी तिवारी जी अब आप अपना भाषण शुरू कीजिये ।

श्री राधा कृष्ण किशोर : सभापति महोदय, मैं अंत में आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि बिहार में तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। एक पटना में, दूसरा उत्तर बिहार में, तीसरा झारखंड क्षेत्र के रांची में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री त्रिवेणी तिवारी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने मित्र रवीन्द्र चरण यादव जी को पहले कहना चाहूंगा ।

'सचिव वैद्य शुरू तीन जो, प्रिय बाल ही भयआस,
राज धर्म तय तीन का, होई ही वेग ही नाश ।'

इसी आसन से यह नियमन हो चुका है कि पहले जमाने में जितने चमचे होते थे मंत्रियों के, नेताओं के सब की प्रोन्नति हो गई है । सब चमचे बेलचा हो गये है। लेकिन कोई सीमा तो होनी चाहिए। किसी न किसी वास्तविकता को तो स्वीकारना होगा। मैं मानव संसाधन मंत्री जय प्रकाश नारायण यादव जी का प्रशंसक हूं । मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। वे उम्र में मुझसे कम हैं। मुझे उम्मीद थी बावजूद इसके कि यह महान कार्य राष्ट्र निर्माण का कार्य बहुत कठिन कार्य है फिर भी बड़ों से सीख कर इस तरह का प्रयास करेंगे जिससे कुरीतियों पर काबू पाया जा सके। कोई आश्चर्य नहीं है :

नहिको वश जनता ही जनमाही,
प्रभूता पाई जासू मद नाही ।'

जैसे ही पावर मिलता है वैसे ही सबको घमंड आ जाता है। इसलिए मैं इनको दोष नहीं देता हूं । नीचे से दुरूस्त करो या ऊपर से दुरूस्त करो । लेकिन इन्होंने शिक्षा को बीच से दुरूस्त करने का काम किया है। कई जगह हमलोगों ने सुना ये पहाड़ के बीच में भैंसे के सिंग को घुसेड़ दिये चाहे सिंग टूटे या पहाड़ टूटे । खैर है पहाड़ ही ढह गया। मैं धन्यवाद देता हूं इन्होंने पहाड़ ढाह दिया । हुजूर इस प्रदेश में 1000 स्थापना के प्रस्वीकृत विद्यालय है। वे विद्यालय गलत कागज पर थे । उन विद्यालयों में 1 लाख छात्र हैं । पहले आपने कहा कि उन छात्रों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन मान्यता प्राप्त विद्यालय से कराया जायेगा, बगल में जो विद्यालय हों वहां से इनका रजिस्ट्रेशन कराया जायेगा। इस

साल आदेश निकाल दिया कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जायेगा, उनका फार्म नहीं भराया जायगा। सभापति महोदय, 1 लाख बच्चे त्रिवेणी तिवारी और एम० एल० ए० के बच्चे नहीं हैं वे उनके बच्चे है। जिनकी वकालत से सुबह से शाम तक करते है। वे गरीबों के बच्चे है। ये कहां से इम्तिहान देंगे। दो दिन समय बचा हुआ है। आपको सोचना होगा कि उन बच्चों का कहां से रजिस्ट्रेशन होगा। आप परीक्षा में कड़ाई कीजिये अच्छी बात है। आप स्थानांतरण कीजिये अच्छी बात है लेकिन जिस रूप में आपने किया है और आज भी कर रहे हैं वह गलत है। मैं उस मिट्टी में पैदा हुआ हूं जिस मिट्टी में यह कहा गया है :

'गरू गोविन्द दोनों खड़े, कांको लागो पांव,
बलिहानी उस गुरू की, जो गोविन्द दियो बताये।'

एक वक्त भगवान शंकर ने कहा था कि गुरू को प्रणाम करके मेरे पास आओ और आप सुबह से शाम तक उस गुरू को गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये शिक्षक नहीं शिक्षा माफिया हैं। माफिया लोग कॉलेज खोले, स्कूल खोले। ये प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और हाई स्कूल के शिक्षक कैसे माफिया हो गये। ये माफिया इसलिए हैं कि एक स्कूल म 10 वर्ष से हैं। आप उनको कहिये कि दूसरी जगह जाकर पढ़ायें। आप उनको अपमानित तो नहीं कीजियेगा। वे शिक्षक हैं और उनको आपने जिस तरह से अपमानित किया उससे क्या पाये। इसलिए क्या, सौदा किये और क्या पायें आप

विचार कीजिये। अभी भी वक्त बचा हुआ है। सभापति महोदय, मैं बहुत साफ कह रहा हूं। आप विचारिये, और विचार ने का शुरूआत एक जिला के विधायकों को और वहां के शिक्षक प्रतिनिधियों को बुलाकर कीजिये। उदाहरण स्वरूप मैं मोतिहारी की बात कहता हूं। मोतिहारी में आजादी के पहले तीन उच्च विद्यालय थे। आज भी वहां उच्च विद्यालय तीन ही है। जबकि वहां की आबादी 14 गुना बढ़ गई है। नये कानून के मुताबिक हम विद्यालय खोल नहीं सकते है। सरकार जो खुले हुए विद्यालय है उन्हीं को सुबह से शाम तक बंद करने में लगी हैं आखिर बच्चे जो हुए वे कहां जायेंगे । हम दोपालियों में वहां के प्रशासकों और शिक्षकों के सहयोग से पढ़ाई करवाते थे। दो पालियों में शिक्षक पढ़ाते थे। 8 बजे से 5 बजे तक । आपने उन शिक्षकों को इधर भेज दिया। एक विषय के चार शिक्षक और छः विषय में एक भी शिक्षक नहीं । मैं क्या जवाब दूंगा। कहां से शुरू कीजिये ये पूछ रहे हैं महासेठ जी यदि संभव हो तो मंत्री जी आप महोसठ जी को एक और विशेषण लगा दीजिये, महासेठ जी। मधुबनी की हालत मोतिहारी से कम बदतर नहीं है। वहां जो शिक्षक गये हैं उन लोगों का कहना है कि विद्यालय में 300 बच्चे हैं और उस विषय के छात्र घूम रहे हैं। कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है। कैसे लोग, कैसे मेधा वाले लोग चुन-चुनकर आये हुए है। तीन चार दिन पहले एक गुरूजी मेरे पास दरख्वास्त लेकर आये हुए थे। उन्होंने कहा कि आवेदन पर अपनी अनुशंसा कर दीजिये। उस आवेदन पत्र को मैंने अपने पास रख लिया। संयोग से जब आवेदन पत्र हमसे कहीं खो

गया। जब वह गुरू जी हमसे आवेदन पत्र मांगने आये तो मैंने कहा कि वह आवेदन पत्र कहीं खो गया है आप दूसरा आवेदन पत्र लिख कर दे दें। उनका नाम गीता सिंह था। उन्होंने पहला जो आवेदन पत्र दिया था उसमें गीता दीर्घीकार लिखा था और बाद में जो आवेदन पत्र पर दस्तखत किया वह हरसीकार से लिखा । मैं यह देखकर भ्रमित हो गया। लेकिन सभापति महोदय, जब मैंने यहां शिक्षा को तीन बार पुलिंग और दो बार स्त्रीलिंग कहते हुए सुना तो मुझे लगा कि वह गुरूजी ने ठीक ही लिखा है। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं क्या हर्ज है एक विंद्यालय को ले ले। मोतिहारी में, कोई किताब ले लें, मैं नहीं कहता हूं कि पढ़ायें लेकिन पहले भी ऐसा होता था हुजूर एक किताब ले लीजिये। आप पढ़ कर उनको लिखने कहिये, आपको जांचने में दिक्कत हो तो किन्हीं से जंचवा लीजिये। पहले भी कर्पूरी जी के समय में ऐसा हुआ है। उस समय एक भी शिक्षक को स्थानांतरित नहीं किया गया लेकिन पूरा वातावरण बदल गया। आप वातावरण बदलिये। लेकिन सभापति महोदय, यह काम शिक्षकों को प्रताड़ित करके नहीं किया जा सकता है। आज बहुत से मदरसा है। वहां के शिक्षकों को 10-10 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। आप क्या उम्मीद करते हैं उन शिक्षकों से कि वे ठीक से पढ़ा रहे होंगे। जो गलत रूप में स्कूल है उसको बंद कीजिये ।

लेकिन जो ठीक है उसको तो ठीक से चलाइये । जनता ने आपको इतना प्रबल बहुमत दे दिया हैं आप जनता से जो कह कर आये हैं उसको पूरा तो कीजिये। अगर पूरा नहीं कर पाये हैं,

तो उसको बुलाकर समझा तो दीजिये। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि निम्न बिन्दुओं पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। एक तो यह कि इस प्रदेश में वित्त रहित शिक्षा नीति को पूरा समाप्त कर देना चाहिए । सभापति महोदय, ये कहेंगे कि सरकार को पैसा नहीं है तो भारत सरकार जितना पैसा देती है और सरकार जितना शिक्षा शेष के रूप में वसूलती है उससे वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त किया जा सकता है। स्भापति महोदय, जहां उच्च विद्यालय की संख्या 3626 है और प्लस टू की संख्या 253 है और विद्यार्थी 1 करोड़ 29 लाख है। एक उच्च विद्यालय में यदि 3,300 विद्यार्थी को पढ़ाने की व्यवस्था हो जाये तो सबका समायोजन हो जायेगा । यद्यपि कोई ऐसा विद्यालय नहीं है पटना कॉलेजिएट स्कूल में भले ही पढ़ाई हो सकती है। आखिर में मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रमंडल के स्तर पर इन तमाम चीजों की समीक्षा करें । शिक्षा विदों को बुलाकर उस इलाके के जो जन-प्रतिनिधि हैं उनको बुलाकर । सब जगह आपने मैनेजिंग कमिटी बना दिया। किसका मैनेजमेंट करेंगे । गुरूजी का । वहां तो कुछ है ही नहीं। हमको आप भेज दीजिये कि बिहार के नगरपालिका को मैनेज कीजिये तो हम डर के मारे नगरपालिका में जायेंगे भी नहीं क्योंकि वहां सफाई मजदूरों को बहुत दिनों से पैसा नहीं मिल रहा है।

यही कह दीजिये कि आप स्थानीय साधन जुटाकर इसको करेंगे। महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक पैसा भी आपने उसमें नहीं दिया है, एक पैसा भी आपको नहीं लगा है और वहां शिक्षकों ने अपने वेतन

से 20 हजार का गेट बनवा दिया। वहां के कर्मचारियों ने 10 हजार का फर्नीचर दिया। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री श्री रामचन्द्र पूर्व जी गये हुए थे उन्होंने देखा। महोदय, एक बात मैं अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं, वहां पर बहुत प्रयास करने के बाद भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की कृपा से एक नवोदय विद्यालय खुला, बहुत कसरत करने के बाद। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि उसके लिए भूखण्ड उपलब्ध करा दिया जाये, कृषि विभाग को निर्देश दिया गया कि 29 एकड़ जमीन दे दीजिये । कृषि विभाग और भी नव संसाधन विभाग ने तय किया कि जमीन दे दिया जायेगा, लेकिन वहां एक घर पड़ा हुआ है और चूहा भी मुश्किल से वहां रहता है। हमलोगों ने कहा कि इसकी मरम्मति कर देते हैं, एक साल चलाइये, अस्थायी रूप से और बाद में आपका भवन हो जायेगा। कृषि विभाग का भवन शिक्षा विभाग में जाना है, 200 रुपया भी कोई नहीं देगा और हमलोग 50 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं, रिपेयरिंग पर। महोदय, वहां के मैनेजर ने कहा कि ज्वाइन्ट डाइरेक्टर देंगे, ज्वाइन्ट डाइरेक्टर ने कहा कि डाइरेक्टर देंगे और डाइरेक्टर के पास गये तो उन्होंने कहा कि हम तो सचिव के यहां बढ़ा देंगे । तो कल मंत्री जी से कहा कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि इस राज्य में मुख्यमंत्री बड़े हैं, शिक्षा मंत्री बड़े है, कृषि मंत्री बड़े हैं, या डाइरेक्टर बड़ा है, या ज्वाइन्ट डाइरेक्टर बड़ा है। महोदय, सितम्बर में इसको शुरू होने है, डेढ़-दो माह रह गया है।

सभापति : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री त्रिवेणी तिवारी : महोदय, बिना आपको साधुवाद किए, कृतज्ञता प्रकट किए कैसे हम समाप्त करें।

सभापति : धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है, जो कहना है आप जल्दी कह दीजिये ।

श्री त्रिवेणी तिवारी : सभापति महोदय, आखिर मैं कहना चाहता हूं कि इधर से भी और उधर से भी आवाज उठी है कि भ्रष्टाचार नहीं है, ट्रांसफर में, लेकिन मैं कहना चाहता हूं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। मैं मंत्री जी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं ।

सभापति : आप कब से भ्रष्टाचार पर बोलना शुरू कर दिए।

श्री त्रिवेणी तिवारी : महोदय, यह तो सार्वभौम हो गया है। तो सभापति महोदय, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और हमारे माननीय मंत्री जी की इसमें मजबूरी है। मजबूरी यह है कि इनके पास एक भी आर० डी० डी० नहीं है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज बिजीलेन्स का नहीं है, आधे आर० डी० डी० दो बार जेल जा चुके है, इनके पास योग्य पदाधिकारी नहीं है, तो ये क्या करेंगे । इसमें जो कानून है उसमें भी डिफेक्ट है, इनको जो एडुकेशन कोड है, पुराने जमाने का है, जिस तरह पी० डब्लू० का कोड चला आ रहा है। महोदय, सत्र अभी लम्बा-चौड़ा है, मैं आग्रह करूंगा कि इस कोड में आवश्यक संशोधन का प्रयास करें और भ्रष्टाचार सभी जगह से हटायें । इस तरह का कोड अगर है तो आप इनको कम्प्यूटराइज कर दीजिये, नहीं तो हमीं लोगों के वेतन से कुछ काटकर कम्प्यूटराइज कर दीजिये ।

सभापति : माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें। श्री के० वी० प्रसाद ।

श्री के० बी० प्रसाद : महोदय, कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए पहले मैं अपनी दो पंक्तियां आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं –

'दिया जो वक्त कहने का शुक्रगुजार है के० वी०,
खड़ा हूं अभी मैं जहां, कभी दावेदार थीं देवी ।

महोदय, इस सरकार की शिक्षा नीति का अंध विरोध करने वालों की मायोपिया, शार्ट-शाइटेडनेस, अल्पदृष्टिता, जो इनकी कम देखने की क्षमता है, वह दूर हो सके, उसका इलाज हो सके, इसके लिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदय, यह ठीक है बिहार में आज शिक्षा की जो स्थिति है वह बर्बाद है, बदहाल है लेकिन, दिस स्टेट ऑफ एडुकेशन इन बिहार

(व्यवधान)

मैं जो बोल रहा हूं, मेरा आग्रह है कि उसको सुनें ।

I will not like to talk, The state of education in Bihar is a bad legacy of the past. It is one of the many missings of the Congress mis-rule, and the black rule of the Congress Party.

तो मैं कहना चाहता हूं कि ये तमाम बातें, ये कांग्रेस के दुष्कर्म और कांग्रेस के कुकर्म, मेरी गुजारिश है, बार-बार गुजारिश है

I will like to be decent and I expect decency from others. All the persons can not understand

english, but I teach english, I understand english, I feel english. But it is the sad part of the house that I have to deliver my speech in english. So, my time should not be wasted. I like to be understood by all the persons, all the legislators. That's why I want to deliver my speech in Hindi.

तो मैं कह रहा था महोदय, इनके कुकर्मो की चर्चा कर देने से क्या हमें फुर्सत मिल जायेगी ? क्या हमें राहत मिल जायेगी ? नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार नहीं, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और हमारी सरकार जिस तरह से यह कहना चाहती है, पहले उसको समझने की जरूरत है और आज जिस रहवर, जिस रहनुमा के माध्यम से हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा है, उसको समझने की जरूरत है, तब हम शियाक्षा को बेहतर समझ सकते है। महोदय, आर्म्स इज ए कैरिश्मेटिक लीडर, लालू यादव इज ए कैरिस्मेटिक लीडर ।

सभापति : आप अंग्रेजी बहुत ज्यादा बोले जा रहे हैं, लिखेगा कैसे ? आप हिन्दी में बोलिये ।

श्री के० वी० प्रसाद : और महोदय, कैरिस्मेटिक लीडर को बिना समझे उनके कार्यो को समझना मुश्किल होगा ।

(व्यवधान)

All the day, I feel hooting, fading be the members, of the members in the house.

तो मैं कह रहा था महोदय, कि आवर्स इज ए कैरिस्मेटिक लीडर, चमत्कारी नेता हैं और चमत्कारी नेता के कार्यो को और उनकी वाणी साधारण रूप से समझी नहीं जा सकती है।

सभापति : आप विषय पर बोलिये, डिमान्ड है आज एडुकेशन विभाग का, आप प्रोफेसर है।

श्री के० वी० प्रसाद : मैं यही बोल रहा हूं महोदय, ये कैरिस्मेटिक नेता हैं और समाज को कैरिस्मेटिक लीडर की जरूरत तब पड़ती है जब समस्या सघन हो जाती है। महान समजाशास्त्री मैकाइवर ने कहा है कि,

"A chardsmatic leader is the product of deep crisis."

और हमारे यहां डीप क्राइसिस है। वह डीप क्राइसिस है वर्ण व्यवस्था की।

महोदय, आज भाजपा है हरिजन की बात करते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि उन्हीं लोगों के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था पैदा हुई उसी के कारण आज लालू यादव जी को रहनुमाई करने की आवश्यकता हुई। महोदय, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री लालू यादव के द्वारा जो कार्य किये गये हैं उनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री त्रिवेणी तिवारी जी ने अभी कहा है कि 'आचांर्य भी कहते जाते हो और अपमान भी करते जाते हो और बातों-बातों में विषभरी बात को कहते जा रह हो।' माननीय सदस्य श्री के० पी० प्रसाद जी उन्हीं का जवाब दे रहे हैं।

सभापति : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री के० वी० प्रसाद : महोदय, लालू यादव की बात को समझने में परेशानी होती है इनलोगों को । लेकिन उन्होंने क्या कहा – 'गाय बकरियां चराती जाओ मुनिया बिटिया पढ़ती जाओ ।' फिर उन्होंने आगे कहा – पढ़ो या मरो । महोदय, जब लालू प्रसाद जी ने चरवाहा विद्यालय खुलवाया तो इन लोगों ने कहना शुरू किया लालू यादव चरवाहा विद्यालय खोलना चाहते है। लेकिन उन्होंने जिस चरवाहा विद्यालय के माध्यम से जनता के बीच में जो मैसेज देने का काम किया उसको इन लोगों ने नहीं समझा, उसके कंसेप्ट को इन लोगों ने नहीं समझा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि लालू यादव जैसे गरीब परिवार का व्यक्ति चरवाहा विद्यालय नहीं खुलवायेंगे तो मोंटेशरी, संत जेवियर और डोनवासको स्कूल खुलवायेंगे । महोदय, तथाकथित जो बड़े लोग है जिसको हमलोग एलिस कहते हैं वे उनके कार्यो को नहीं समझ रहे है। लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति ही गरीब लोगों की परेशानियों को समझते है और उनके दुख को दूर करने का काम कर रहे हैं। महोदय, आज समाज को लालू यादव जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिन्होंने रानी और महारानी को महल में एक साथ बैठाने का काम किया है। सभापति महोदय, महान दार्शनिक थॉमेश हार्डी ने कहा है कि अगर अच्छा व्यक्ति बनना है तो गरीबों के बस्ती से होकर गुजरना होगा।

सभापति : अब आपका समय समाप्त हो गया। माननीय सदस्य अब आप बैठ जायें ।

श्री विश्वनाथ भगत : सभापति महोदय, शिक्षा के संबंध में जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जो शिक्षा नीति है वह तो इससे स्पष्ट होता है कि कदाचार रोकने के लिए इस सामाजिक न्याय की सरकार द्वारा कदाचार मुक्त परीक्षा कराई गई, उससे साबित हो जाता है। यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल विफल रही है। इस तरह यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छी तरह से पढ़ाई सुविधा उपलब्ध कराने में बिल्कुल विफल रही है। यही कारण है उत्तर बिहार में रिजल्ट हुआ वह साबित करता है कि बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितना विफल रही है। झारखंड क्षेत्र में कदाचार रहित परीक्षा पहले से होती आयी है लेकिन झारखंड क्षेत्र में ऐसे भी प्राथमिक और उच्च विद्यालय है जिसके साथ शुरू से ही सौतेलापन व्यवहार किया गया है। आज जिस रफ्तार में शिक्षकों का स्थानान्तरण हुआ है । उसमें बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहां से सारे शिक्षकों को दूसरे जगहों हस्तांतरण कर दिया गया है और बहुत ऐसे विद्यालय है जहां पर मात्र दो-चार शिक्षक ही है। जैसे रांची जिला के लाकून प्रखंड में राज विद्यालय है जहां पहले 10 शिक्षक थे उन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया । लेकिन उसके बदले मात्र चार शिक्षकों को वहां पर पदस्थापित किया गया है। उस विद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका विषय क्या होगा ? उसी तरह से प्राथमिक विद्यालय में विशेषकर झारखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में जो यूनिट है उस यूनिट के आधार पर कहीं भी शिक्षक नहीं है। महोदय, शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं वे आज शिक्षा की

ओर ध्यान नहीं देकर आज वे राजनीति कर रहे हैं। और शिक्षकों को परेशान करते हैं। आज उसी परेशानी के चलते शिक्षा का स्तर दिनों-दिन खराब होते जा रहा है।

महोदय, उसी तरह से झारखंड क्षेत्र के विश्वविद्यालय को देखेंगे तो वहां का सबसे पुराना विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय है जिसको आज तक जमीन मुहैया नहीं कराया गया है। जिस महाविद्यालय की अपनी जमीन नहीं होगी तो उस महाविद्यालय की क्या स्थिति होगी, यह आपके सामने है। उसी तरह से झारखंड क्षेत्र में सिद्ध कान्हू महाविद्यालय पिछले छः वर्षो से स्थापित किया गया है लेकिन उसको भी आज तक एक इंच जमीन नहीं मुहैया कराया गया है और उस विश्वविद्यालय को कुलपति को पदस्थापित किया गया है और न वहां रजिस्ट्रार को ही पदस्थापित किया गया है। ये विश्वविद्यालय ऐसी स्थिति से गुजर रही है तो उसी से यहां के शिक्षा का अन्दाज लगाया जा सकता है। शिक्षा विभाग शिक्षा की प्रगति के लिए कितना प्रयत्नशील है और उसको सुधारने के लिए कितना कारगर कदम उठाया है ? इतनी ही बात नहीं है महोदय, हमलोगों के झारखंड क्षेत्र में इंटरमीडियेट कौंसिल, बिहार परीक्षा बार्ड और मदरसा बोर्ड को खोलने के लिए मांग किया गया था जिसके लिए घोषणा भी हुई लेकिन वहां पदाधिकारियों की पदस्थापना आज तक नहीं की गई है जिस कारण उनको जो वहां पर ब्रांच औफिस खोला गया था वह आज पोस्ट औफिस के रूप में काम कर रहा है। यदि वहां पर पदाधिकारियों को पदस्थापित किया जाता तो वहां के छात्रों को सुविधा होती। यह कार्यालय

सही संलामत चलता तो झारखंड क्षेत्र में कदाचार रहित परीक्षा होती और कदाचार मुक्त परीक्षा से छात्र आते। महोदय, इतनी ही बात नहीं है झारखंड क्षेत्र में जो प्रोजेक्ट विद्यालय है उसके लिए इस हाउस में कई बार आवाज उठाया गया लेकिन सरकार इस ओर आज तक ध्यान नहीं दी ।

इसके बारे में कुछ नहीं सोचा गया। जो प्रोजेक्ट विद्यालय है और उसमें कार्यरत जो शिक्षक और कर्मचारी है वे 10 वर्षो से भूखे और नंगे शिक्षा दे रहे है। इस तरह से हमारे गुमला जिला के सिमडेगा अनुमण्डल में चार ऐसे अल्पसंख्यक विद्यालय हैं जहां के शिक्षकों को 3 वर्षो से वेतन नहीं मिला है और न तो नीति का निर्धारण हुआ है। इस तरह शिक्षा विभाग के द्वारा झारखंड क्षेत्र में खेलवाड़ किया जा रहा है। अब खेल का जहां तक सवाल है तो सही मायने में देखें, आज झारखंड क्षेत्र की नीति ही ऐसी है जो खिलाड़ी पैदा करने की विशेषता रखता है और इस सरकार की नीति इस तरह की रही है कि भाई भतीजावाद के चलते झारखण्ड क्षेत्र के जो अच्छे खिलाड़ी है उनको आने का मौका दिया जाता है।

सभापति : अब आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठ जाइये।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आज बहुत ही महतवपूर्ण विषय पर बात हो रही है। मैं दोनों पहलुओं को एक-एक करके रखना चाहता हूं। जहां एक ओर वर्तमान सरकार ने शिक्षा में पिछले वर्ष की तुलना में बजट में कुछ बढ़ाया है लेकिन इसके बावजूद भी जितना है फिर भी कम है। सूबा

बिहार जो शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है इससे काम नहीं चलेगा । डाटा के भ्रमजाल में मैं नहीं जाना चाहता हूं लेकिन हिन्दुस्तान में बहुत से ऐसे सूबे हैं जहां बजट का 25 से 30 प्रतिशत रुपया शिक्षा पर खर्च होता है जबकि हमारे यहां 4.75 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रहे है। महोदय, कुछ बातें आई है जिनको मैं दुहराना नहीं चाहता हूं लेकिन मूल रूप से जो आज बिहार की वर्तमान सूबाई हुकूमत है और जो उनके उद्देश्य है नारा है सोशल जस्टिस का, उस ओर इशारा करना चाहता हूं कि आखिर इसका इम्पलीमेन्टेशन कैसे होगा ? मेरा सुझाव है कि जैसी बात हम कहते है, उन गरीबों, भेड़ बकरी और सूअर चराने वाले के बच्चों को शिक्षा मिले, इस दिशा में विचार करना होगा और इनको शिक्षा तभी आप दे सकते है जब मिडिल स्कूल स्तर तक उन्हें दिन के भोजन की गारंटी मिले, कपड़ा देना होगा और उन्हें किताब कापी मुहैया कराना होगा और तब जो सतही जनता है इनके बाप दादा हल जोतते रहे है। हम उनके बच्चों को शिक्षा दे सकते है और तभी हम सोशल जस्टिस लागू कर सकते है। इस दिशा में सरकार को गम्भीरता से सोचना होगा तभी आपका नारा सही साबित हो सकता है। आप जो फीस में बढ़ोत्तरी कर रहे है। आप उन्हें वापस करें अन्यथा जो गरीब गुरबा के लड़के हैं इम्तिहान में अपियर नहीं हो सकते हैं। महोदय, इस तरह मैं एक बात की ताइद करता हूं कि कदाचार को बहुत हद तक इन्होंने रोका है, शिक्षा माफिया को बहुत हद तक दबाया है, यह पोजिटिभ ऐक्शन है लेकिन इससे ही काम नहीं चलेगा। आज स्थिति क्या है । आज जितने

भी बहाली के आंकड़े दिये गये हैं लेकिन इनके ही आंकड़े के मुताबिक जितने शिक्षक के सृजित पद हैं प्राथमिक विद्यालयों में अभी भी उन शिक्षकों की कमी है। 13 हजार विद्यालय ऐसे हैं जहां सिर्फ एक ही शिक्षक कार्यरत हैं ।

इस तरह से जो आपके हायर एजुकेशन है उसमें नीजिकरण को कैसे समाप्त किया जाय इस दिशा में कदम उठाना पड़ेगा। आज हायर एजुकेशन की स्थिति क्या है, चाहे सत्तापक्ष के लोग हैं या विपक्ष क लोग हैं, बहुतेरे लोग हैं, जो छात्र आन्दोलन के गर्भ से पैदा हुये है। आज आपका डेमोक्रेटिक सेटअप चरमरा गया है। सिनेट, सिन्डिकेट और छात्रसंघ का चुनाव वर्षो-वर्ष से नहीं हुआ है। ये इसके जम्हुरी फन्यशनिंग पर रोक लगा दिया है। हायर एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हमारे नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग में अहम भूमिका का निर्वाह करता है। हम अगर इसके डेमोक्रेटिक सेटप आपको बहाल करते हैं तभी हमारा जो मुल्क है और इस सूबे बिहार की आज जो फिजा है, जो हमारे वतन दुश्मन ताकत है, जो हमारी जम्हूरियत और एकता और कौमी एकता को तहस-नहस करना चाहते हैं, आप ऐसी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर हम हायर शिक्षा को जनवादी नहीं कर सकते है। अगर हम शिक्षक और छात्र संघ का चुनाव नहीं करते हैं तो हम जम्हुरियत की हिफाजत नहीं कर सकते है।

सभापति महोदय, हमारा एक सुझाव है कि गणेश शंकर विद्यार्थी कमीशन बना था [illegible] रिकोमेन्डेशन में, हम यह [illegible] चाहते हैं कि क्या सरकार उस दिशा में [illegible]शंसा को

लागू करना चाहती है। सलेबस कुछ हल्का होना चाहिये। एक महत्वपूर्ण बात है कि बिहार सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति रखनी होगी। यह जो स्कूलों में आर० एस० एस० के लोग कवाएद कराते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाना होगा। किसी भी स्कूल में आर० एस० एस० का कवायद नहीं होगा।

सभापति : अब आपका समय समाप्त हो गया, बैठ जाइये। अब इनकी बात नहीं लिखी जायेगी ।

श्रीमती सीता सिन्हा : सभापति महोदय, मैं सरकार की ओर से शिक्षा बजट जो पेश किया गया है उसके समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। महोदय, पिछले 6 सालों से जनता दल की सरकार ने शिक्षा जगत में क्रान्ति लाने का काम किया है और वह सराहनीय काम रहा है। शिक्षा जगत में बिहार सरकार का काम सराहनीय रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो नई योजनायें बनाई गई हैं जो अनौपचारिक शिक्षा में 50 हजार केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिसमें 300 की आबादी पर सामाजिक दृष्टि से गरीब लड़कों के लिये उनके बीच एक स्कूल खोलने का काम किया गया है।

सभापति महोदय हमारी सरकार की ओर से बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहन देने के लिए एक रुपया प्रति दिन प्रति बच्चा देने का प्रावधान है और जो बच्चे स्कूल नहीं जाते है उन्हें दंडित करने का प्रावधान किया है । सभापति संविधान में शिक्षा को समानता का अधिकार दिया गया है लेकिन वर्षो बीत जाने के बाद भी समानता का अधिकार नहीं मिला है।

शिक्षा के बिना किसी भी क्षेत्र में विकास संभव नहीं है, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में बिहार पिछड़ा है और बिहार में अभी 38.48 प्रतिशत लोग शिक्षित है। सभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहती हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बहालिया हुई है वह आज तक कभी नहीं हुई थी। 25 हजार शिक्षकों की बहाली की गयी है और 4 हजार शिक्षकों की, व्याख्याता की बहाली हुई है, चार सौ उर्दू शिक्षकों की बहाली की गयी है ओर 3600 अनु० जा० औरर अनु० ज० जा० के लोगों की बहाली की गयी है। 50 हजार स्वयंसेवी एवं 50 हजार शिक्षा सेवियों का चयन किया गया है। शिक्षा में सुधार लाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री ने जो कदम उठाये हैं, वह स्वागत योग्य हैं । महोदय, शिक्षा में सुधार लाया गया है एवं विरोधी दल के जो लोग हैं, उनको भी कुछ इसके लिए तकलीफ सहना पड़ेगा। वर्षो से एक ही स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे थे, वे पढ़ायेंगे क्या ? पढ़ाने के बदले राजनीति कर रहे थे । अपने हाल रोजगार में लगे हुए थे। उनलोगों को हमारी सरकार ने स्थानातरित करने का काम किया है। यह शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। सभापति महोदय, बिहार में आज परीक्षा फल का प्रतिशत कम रहा है इसके पीछे क्या कारण है ? आज से पहले परीक्षा में 90 प्रतिशत 45 प्रतिशत रिजल्ट होता था। इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ है, इसी कारण परीक्षा फल का प्रतिशत कम रहा है । मैट्रिक की परीक्षा में 13 प्रतिशत रिजल्ट हुआ, आई० एस० सी० की परीक्षा में 1 लाख, 61 हजार छात्र शामिल हुए जिसमें मात्र 14

हजार 801 छात्र सफल हुए। आई० कॉम० की परीक्षा में एक लाख 24 हजार स्टूडेंट सम्मिलित हुए जिसमें मात्र हुए 13 हजार स्टूडेंट सफल हुए।

सभापति : सब आप ही बता दीजियेगा तो सरकार क्या जवाब देगी ?

श्रीमती सीता सिन्हा : सभापति महोदय, व्याख्याता की पात्रता परीक्षा हुई जिसमें 55 हजार स्टूडेट शामिल हुए, जिसमें से 1760 सफल हुए। सभापति महोदय, हम सदन को बताना चाहते हैं कि जब राज्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं होती हैं प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उसमें बिहार के स्टूडेंट कम जाते हैं इसका कारण है कि चोरी करके यहां स्टूडेंट परीक्षा पास करा लेते थे, यहां की डिग्री का बिहार से बाहर ले जाने पर भैल्यू नहीं मिलता था। यहां के स्टूडेंट को लोग दूसरे दृष्टि से देखा करते थे। इस बार कदाचार मुक्त परीक्षा बिहार में हुआ है, बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ है। हमलोगों को थोड़ी तकलीफ हुई है कि हमारा बच्चा फेल हो गया है लेकिन इस बात का गौरव है कि बच्चों के पढ़ने के प्रति जागरूकता बढ़ी है, पढ़ाई के प्रति छात्र उत्सुक हुए हैं सभापति महोदय, गरीब के बच्चे खेलते हुए पढ़ेंगे, इसके लिए 109 चरवाहा विद्यालय राज्य में खोला गया है। अभी वर्त्तमान में बिहार में प्राथमिक विद्यालय की संख्या 51 हजार 319 है, मध्य विद्यालय की संख्या 12 हजार 470 है, विश्वविद्यालयों की संख्या 12 है, जिसमें 5 नवसृजित महाविद्यालय भी है। सम्बंद्धता प्राप्त महाविद्यालयों

की संख्या 437 है एवं अंगीभूत महाविद्यालयों की संख्या 305 है।

श्री राजा राम सिंह : सभापति महोदय, उन दिनों बिहार की सरकार जिस बात के लिए सबसे ज्यादा अपना पीठ ठोक रही है कि हमने कदाचार मिटाया है।

सभापति : कभी तो राजा राम बाबू भाषण देने में नर्म रहिये ।

श्री राजा राम सिंह : सभापति जी, आप ही की टोका टोकी में 2 मिनट चला जाता है। सभापति ज़ी, सरकार इस बात के लिए अपना पीठ ठोक रही है कि हमने कदाचार मिटाया है और ठीक इसी बात से उसकी खामियां उजागर होती है। बिहार में पठन-पाठन की क्या स्थिति है। इन्टरमीडियेट की और मैट्रिक की परीक्षाफलों ने इस बात को बड़े पैमाने पर उद्घाटित किया है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लड़के प्राईवेट स्कूल में चले जाते हैं वे ही बेहतर कैसे हो जाते हैं और सरकारी स्कूल में रहते हैं तो वे खराब हो जाते है। पांच साल के लड़के, 10 साल के लड़के अगर खराब हो रहे है। तो मैं कहना चाहता हूं कि उसके पिता भी अच्छे नहीं माने जा सकते और यही व्यवस्था खराब बच्चे पैदा कर रहे हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि लगातार छात्रों को खराब कहना गैर वाजिब है। अभी हाल के दिनों में अंग्रेजी अखबार में हमारे मुख्यमंत्री की टिप्पणी प्रकाशित हुई थी। कोई मानव संसाधन की राज्य मंत्री जिस दिन बनी थी उसी दिन

बिहार में परीक्षाफल प्रकाशित हुआ था। बिहार सरकार ने कहा कि हमने मेरिट पर परीक्षाफल प्रकाशित किया है और दोनों मेरिट की तुलना हुई। आज जब आपकी राजनीति मुख्य रूप से हिन्दुस्तान में एक नया रास्ता दिखाने की बात करती है तो आज राजनीतिज्ञों का नाम ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है तो आप नये बिहार में नया रास्ता क्या दिखायेंगे इसलिए कहना है कि इसमें बुनियादी सुधार की जरूरत है। जहां तक शिक्षा ऐसा मामला है इसमें हमारा कहना है कि धन आधारित शिक्षा नीति को समाप्त करना होगा। आज जो ट्रेण्ड देख रहे हैं कि प्राईवेट एजुकेशन और धीरे-धीरे पैसे के आधार पर शिक्षा की प्रवृति बढ़ती चली जा रही है। इधर सरकारी शिक्षा खत्म होते जा रही हैं यही बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर समय रहते अगर रोक नहीं लगायी गयी तो बजट दर बजट आप पेश करते रहे इस खतरनाक प्रवृति से बचा नहीं जा सकता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मामले में करोड़ों रुपये बहाए गए है लेकिन वे पैसे भ्रष्टाचार का शिकार हुए। साक्षरता के मामले में बहुत-बढ़त हासिल नहीं की बिहार ने। लालू जी ने चरवाहा क्रान्ति की थी। लेकिन शिक्षा रिपोर्ट में उसके बारे में कुछ नहीं है कि उस क्रान्ति के बारे में क्या उपलब्धि हासिल हुई । हर बार केवल अपनी पीठ मत पथपाईये। चरवाहा विद्यालय का क्या हुआ। इसमें कोई चर्चा नहीं है। कितनी उपलब्धि हुई, इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हाल के दिनों में 90 से 95 तक में राष्ट्रपति जी के पास जो शिक्षकों के नाम भेजे जाते थे राष्ट्रपति पुरस्कार

के लिए उर्दू, फारसी के, अरबी के, संस्कृत के किसी भी शिक्षक का नाम 5 वर्ष से नहीं भेजा गया। इतने वर्ष में किसी भी शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार विभाग से नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि आज बिहार में उच्च शिक्षा में जो अराजकता मची हुई है जिस पर कोई ध्यान नहीं है। कोई कुलपति एक्सेंशपन पर काम कर रहे हैं, कई प्राचार्य कार्यकारी है, फुल फलेजेड नहीं है। विश्वविद्यालयों में फंड की कमी है । हमारे विश्वविद्यालयों में डेमोक्रेटिग ढंग से फंक्शनिंग लागू नहीं है। न स्टूडेंट यूनियन है, न कहीं सिन्डिकेट है और न कहीं सिनेट हैं और इसका यही अंजाम है कि आज पूरे शिक्षा जगत में एक एनार्की फैली हुई है। छात्र की भागीदारी नहीं है, शिक्षकों की भागीदारी नहीं है, कर्मचारियों की भागीदारी नहीं है। अगर शिक्षा को बेहतर बनाना चाहते हैं तो तमाम मुद्दों पर ध्यान देना होगा। आज केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार चल रही है और बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। इसके लिए यहां से एकमुश्त प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए और उस पर दबाव बनाया जाना चाहिए कि वहां पर एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो। हमारा सायंस कॉलेज, हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारा पटना कॉलेज जो एक समय में हिन्दुस्तान के प्रमुख कॉलेजों में हुआ करता था आज उसकी स्थिति क्या है। आज हमारे छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में, बंगलोर में, जे० एन० यू० में जा रहे है, करोड़ों रुपये इस बिहार के आज बाहर जा रहे है। हम अपने राजस्व की बचत करें और एक ऐसे शिक्षा

का माहौल बनाये, ऐसा उच्च शिक्षा दें जिससे कि हम यहां के छात्रों को आगे पढ़ा सके । शोध के मामले में हाल में मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक रिटायर्ड कुलपति से मिला उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि बिहार के लड़के बहुत औरिजनल माईन्ड के हुआ करते है। मैथमेटिक्स में पूरे हिन्दुस्तान में परन्तु खेद है कि पटना विश्वविद्यालय में शोध का काम खत्म हो रहा है। शोध कार्य नहीं हो रहा है, प्रयोगशाला बंद हो रहा है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अगर आप शिक्षा का उत्थान चाहते हैं तो इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दीजिये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से अंत में यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास करें ।

'जलाते चलो शिक्षा का दिया घर-घर ।

तभी तो घरों के अशिक्षा का अंधेरा मिटेगा ।''

श्री शकुनी चौधरी : सभापति महोदय, मानव संसाधन विभाग के संबंध में जो कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य, श्री देव दयाल ने लाया है उसके पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

सभापति महोदय, पिछले विधान सभा सत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री ओर शिक्षा मंत्री द्वारा यह स्पष्ट घोषणा हुयी थी कि जो 25 हजार शिक्षकों की बहाली हो रही है हर हालत में एक शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालय की दो शिक्षक विद्यालय के रूप में परिणत कर देंगे लेकिन अभी तक यह नहीं हुआ है। हम

तारापुर विधान सभा क्षेत्र में ऐसे 17 स्कूल है जहां पर एक ही शिक्षक है। मैं शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि वे किसी भी हालत में दो शिक्षकीय विद्यालय करें ।

सभापति महोदय, इंटरमीडियेट शिक्षा परिषद में किस तरह की अवैध नियुक्तियां हुयी है, इसका आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। महोदय, 300 अवैध नियुक्यिां 15-15 हजार रु० लेकर हुयी है और इस तरह 300 अवैध नियुक्ति हुयी है। एक भी जो उसमें नियुक्ति हुये हैं वहां पर काम नहीं करते है। बल्कि दूसरे के घर में जाकर काम करते है। यह शर्म से डूबा देती है इंटरमीडियेट शिक्षा परिषद को ।

महोदय, जहां उच्च शिक्षा विद्यालय की जब बात करते हैं उसके रिपेयर की बात स्कूल निर्माण की बात करते हैं शिक्षा मंत्री तो बताने का कष्ट करें कि वहां इसके लिए प्रावधान किया है उच्च् विद्यालय भवन के निर्माण के लिये, रिपेयर के लिए।

सभापति महोदय, आप भी जानते हैं f क पहले गांव के लोग पैसा चंदा के रूप में इकट्ठा कर स्कूल भवन का निर्माण किया था वह काफी पुराना हो गया, खपड़ैल का स्कूल है पुराना होने की वजह से छत चूने लगा है, टूटने लगा है। लेकिन एक भी पैसा उच्च विद्यालय को नींव निर्माण के लिये शिक्षा विभाग के माध्यम से नहीं मिलता है जिससे उसके छत की मरम्मति करायी जा सके या नया भवन बनाया जाय। मैं शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि भवन निर्माण के मामले में अभी प्राथमिक विद्यालय के भवन को प्राथमिकता दी गयी है लेकिन उसके साथ-साथ मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के भवन भी

काफी खराब स्थिति में है इसलिये उन विद्यालय भवनों का भी निर्माण कराया जाय उसकी रिपेयरिंग कराया जाय, प्रावधान किया जाय।

सभापति महोदय, अभी शिक्षा समिति जो बनायी गयी है आप आश्चर्य करेंगे कि वह शिक्षा समिति सिर्फ नाम मात्र का है। सिर्फ यहां से कागजी कार्रवाई हुयी है कोई मीटिंग आज तक उसकी नहीं हुयी है, विधायकों को नहीं बुलाया गया है और न उस समिति के सदस्यों की मीटिंग के लिये बुलाया गया है।

उसी तरह उच्च विद्यालयों के लिये प्रबंधन समिति बनायी गयी है लेकिन उसके क्या कार्य होंगे यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है।

सभापति : उसमें लिखा हुआ है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है।

सभापति : हुआ है। लेकिन जब आपलोगों ने प्वाइंट आउट कर दिया है तो मंत्री एक एक कौपी अभी सदस्यों को भिजवा देंगे ।

श्री शकुनी चौधरी : सभापति महोदय, पटना में ही जितने महाविद्यालय के शिक्षक हैं, कस्टीच्यूएंट कॉलेज के शिक्षक हैं वे हर जगह प्राईवेट इंस्टीच्यूट चलाते हैं और उसमें ज्यादा समय देते हैं और पढ़ाने का काम करते है। जबकि कॉलेज में कम समय देते है जिस तरह से माननीय स्वास्थ्य मंत्री

ने निर्णय लिया है कि जो डाक्टर अस्पतालों में काम करते हैं वे किसी भी हालत में प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे । उसी तरह हम शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं कि आप भी शिक्षकों के संबंध में निर्णय लें कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीच्यूट में पढ़ाने का काम बंद करे। महोदय, मुंगेर जिला में अभी 300 अवैध नियुक्तियां हुयी है। 117 व्यक्तियों से 35-40 हजार रु० लेकर नियुक्तियां की गयी है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री के कोई व्यक्ति हैं लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि शिक्षा मंत्री के ऐसे लोग बहाल हैं जिनका नाम लेंगे तो शर्म से सर झुक जायेगा ।

सभापति : आप समाप्त करें ।

श्री शकुनी चौधरी : महोदय, हमारी बात सुनिये तो ।

सभापति : सुन तो लिया। आप बैठ जाइये ।

श्री श्याम रजक : सभापति महोदय, मैं शिक्षा बजट के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी ने जो क्रांतिकारी संकल्प लिया है उसके लिये विरोधी पक्ष को खासकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को शाबाशी देना चाहिये थी। लेकिन उन्होंने कटौती का प्रस्ताव देने का काम किया है।

सभापति महोदय, जहां हमारे शिक्षा मंत्री, श्री जय प्रकाश नारायण यादव जी ने शिक्षा के संबंध में जो संकल्प लिया है,

काम किया है वह सराहनीय है। हमारे शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने झुग्गी झोपड़ी में जाकर पढ़ने लिखने वाले बच्चों को निकाल कर स्कूल में एडमिशन दिलाने का काम किया है। वैसे बच्चों जो स्कूल क्या है नहीं जानते थे, स्कूल उनके जीवन के लिये स्वप्न मात्र था वैसे बच्चों को स्कूल भेजने का काम किया है। जो बच्चे एकलव्य की संस्कृति के अंतर्गत अंगूठा कटवाकर झापड़ियों में रहने का काम करते थे वैसे बच्चों को हमारे शिक्षा मंत्री ने स्कूलों में दाखिल दिलाने का काम किया है। इस तरह उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किया है।

महोदय, पहले बड़े-बड़े लोगों के नाम पर विद्यालय / महाविद्यालय खोले जाते थे लेकिन बिहार में हमारे शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, श्री लालू प्रसाद यादव ने सिद्धू कानू महाविद्यालय, तिलका मांझी महाविद्यालय तथा भीमराव अम्बेदकर के नाम पर महाविद्यालय का नाम दिया वहीं भारतीय जनता पार्टी का सर शर्म से झुक जाना चाहिये था । महाराष्ट्र में दलित लोगों ने भीमराव अम्बेदकर के नाम पर विश्वविद्यालय का स्थापना होना चाहिये यह मांग करते रहे लेकिन वहां की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। इस पर बी० जे० पी० का सर शर्म से झुक जाना चाहिये ।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि जो निजी कोचिंग संस्थान के दुकान चल रहे हैं उसे बंद किया जाय। उसको बंद करने के लिये शिक्षा मंत्री को कुछ करना चाहिये। हमारे दल के यादवेन्दु, राजेश टाइगर, कौशल जैसे विद्यार्थी शहीद हुए है । निजी कोचिंग संस्थानों को बंद करने के

लिये उन्होंने अपने प्राणों की आहूति दी। इसलिये शिक्षा मंत्री निजी कोचिंग संस्थान पर पाबंदी लगाने का काम करें ।

सभापति महोदय, पटना में नवोदय विद्यालय खुला हुआ है लेकिन उसके लिये जमीन नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि वे तत्काल नवोदय विद्यालय के लिये जमीन उपलब्ध करा दें ताकि नवोदय विद्यालय का गठन हो ।

सभापति महोदय, मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो विद्यालय आर० एस० एस० के लोग सरस्वती शिशु मंदिर के नाम पर खोले हुये है जिससे धार्मिक वैमनस्यता फैल रहा है वैसे लोगों पर तत्काल अंकुश लगाने का काम सरकार करे । वैसे स्कूलों को तत्काल बंद करने का काम सरकार करे।

सभापति : अब आप समाप्त करें ।

श्री श्याम रजक : सभापति महोदय, सरस्वती शिशु मंदिर, वनवासी कलयाण केन्द्र के नाम पर विद्यालय खोले गये है। जो धार्मिक आधार पर खोले गये है।

सभापति महोदय, जिस तरह से शेडयुल कास्ट और शेडयुल ट्राईब का बैकलॉग भरने का काम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसके लिये विपक्ष के लोगों को धन्यवाद देना चाहिंये ।

सभापति : ठीक है, धन्यवाद । बहुत बढ़िया । श्री टेकलाल महतो ।

श्री राजेन्द्र प्र० सिंह : सभापति महोदय, हमारा बोलना यह है, जिसकी चर्चा आयी है, माननीय शिक्षा मंत्री ने पत्र

निर्गत किया था और जिसमें इनका यह निर्देश था कि स्थानीय विधायक अपने क्षेत्र के भीतर जितने उच्च विद्यालय हैं, उनके स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में वहां प्रबंध समिति का गठन होगा, लेकिन हमारे यहां बेगुसराय क्षेत्र के भीतर जितने भी शहर में अच्छे स्कूल पड़े हैं, वहां पर इनके निर्देश के आधार पर या अधिकारियों के किस पत्र के आधार पर बी० पी०, कॉलेजियेट, जे० के० आदि उच्च विद्यालयों में एम० एल० सी० लोगों की अध्यक्षता में मैनेजिंग पथ कमिटी गठित करने का काम किया है।

सभापति : वह भी विधायक है। दोनों विधायक होते है।

श्री राजेन्द्र प्र० सिंह : महोदय, लेकिन विधायक को अध्यक्षता देनी थी। मेम्बर के रूप में उन्हें देना था। डबल स्टैंडर्ड हो रहा है। उसे एक कंस्टीच्यूएंसी के एम० एल० ए० को देते हैं और किसी को नहीं। किस आधार पर ऐसा किया गया है, यह बता दें। एक स्टैंडर्ड रहना चाहिये, पूरे बिहार का ।

सभापति : मंत्री जी, इनकी मांग है कि विधायक के निर्वाचन क्षेत्र में विधायक ही रहें । उनके निर्वाचन क्षेत्र में एम० एल० सी० नहीं रहे । सुन लिया है । मंत्री महोदय ने, जवाब दे देंगे ।

महतो जी, जरा कृपा किया करिये। आप अपना नाम बराबर लिख दिया करते है। पुराना रेक़र्ड पढ़ते होंगे तो डिमांड एक ऐसी चीज है, जब श्री बाबू को भी कपिल देव बाबू को 14-15 डिमांड में से एक दिन बोलने के लिये मिलता था । एक ही आदमी एक्सपर्ट हो गये और हर डिमांड पर बोलते रहियेगा।

आप अपना नाम दे दिया। वैसे हमको क्या एतराज है। और माननीय सदस्य को देना चाहिये।

(व्यवधान)

दो ही मेम्बर रहें तो उनको भी दीजिये। हमने जो मुनासिब समझा, कहा आपको। डिमांड बहुत इम्पॉर्टेन्ट होता है विधान सभा में ।

श्री टेकलाल महतो : सभापति महोदय, शिक्षा मंत्री जी निम्नलिखित बिंदुओं पर जवाब देते समय विचार करेंगे ।

117 उच्च विद्यालय जो बिहार में, जिसके लिये स्पेशल बोर्ड का गठन हो चुका है, और स्थापना की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, क्या वैसे विद्यालयों को अधिग्रहण सरकार करना चाहेगी ? प्रत्येक प्रखंड में कम-से-कम चार उच्च विद्यालय सरकारी कोष से चलाया जायेगा, क्या वैसे प्रखंड जहां चार हाई स्कूल नहीं खोले गये हैं खोलने का सरकार काम करेगी ? पंडित जवाहर लाल नेहरू का सपना था कि 300 से 500 की आबादी वाले गांव में कम से कम एक प्राथमिक पाठशाला खोलेंगे । मेरे क्षेत्र में उच्च विद्यालय का घोर अभाव है। क्या वित्त रहित उच्च विद्यालय का निबंधन करने का सरकार आदेश देगी ?

महोदय, विशेष शिक्षा केन्द्र की घोषणा गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसी सदन में की गयी, लेकिन आज स्थिति है, सुचारू रूप से संचालित करने का कार्य अब क्या सरकार करेगी ।

दोहरी शिक्षा नीति जो हमारे बिहार में चल रही है, इसको खत्म करने का काम क्या सरकार करेगी ? दोहरी शिक्षा नीति के चलते गरीब के बच्चे, बिहार के बच्चें, जिसकी चर्चा आप करते हैं वे प्राईमरी स्कूल में बिहार बोर्ड के तहत पढ़ते हैं और बड़े-बड़ें लोगों के बच्चे इंगलिश स्कूल में पढ़ते है। इसके कारण उनको अच्छे मार्क्स आते हैं और अच्छे से अच्छे कॉलेज में ऐडमिशन हो जाता है, जबकि गरीब के बच्चे फेल हो जाते है।

महोदय, छोटानागपुर संथालपरगना में हजारीबाग को कमिश्नरी तो बना दिया, लेकिन वहां मात्र एक ही कॉलेज है हजारीबाग में सेंट कोलम्बस कॉलेज तो बना दिया, लेकिन वहां बिनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना तो जरूर की गयी, लेकिन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना नहीं की गयी है।

महोदय, मंत्री महोदय का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा कि हजारीबाग में जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय में जो कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से कार्यरत है । शिक्षकों का तो तबादला जरूर किया, लेकिन जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में जो ऐसे कर्मचारी है, उनका स्थानांतरण आप कीजिये ।

महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, जो प्राईवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उन स्कूलों को आपने पंजीकृत करने की इजाजत नहीं दी है। हजारीबाग जिला के चुरचू प्रखंड, जो आदिवासी बहुल प्रखंड हैं, वहां आज तक उच्च विद्यालय नहीं बन पाया है। तो महोदय, ये कहते हैं कि गांव में, देहातों में स्कूल खोलेंगे तो मैं पूछना

चाहता हूं कि क्या चुरचू प्रखंड मुख्यालय में उच्च विद्यालय खोलेंगे । यह प्रखंड आदिवासी बहुल प्रखंड है।

महोदय, आज बिहार के एक्जामिनेशन बोर्ड की क्या हालत है ? सचिव और चेयरमैन के अन्तर्द्वन्द के कारण कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है; परीक्षा भी ठीक ढंग से संचालित नहीं हो पा रही हैं

सभापति : ठीक है। अश्विनी कुमार चौबे ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : सभापति महोदय, आज शिक्षा बजट जो शिक्षा मंत्री ने पेश किया है, हम उसके विरोध में और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये आपके आदेश से खड़े हुये है।

महोदय, शिक्षा समाज का दर्पण होता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से शिक्षा का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, लगता है शिक्षा को जिस प्रकार से आगे बढ़ने के लिये तत्पर होना चाहिये था, आज निश्चित रूप से वह समाज के अन्दर कमी है। सरकार जिस शिक्षा को लेकर चली है, मुझे विश्वास है, सन् 74 के आंदोलन के हमारे जेल के साथी रहे हुए, मित्रवत् जय प्रकाश जी शिक्षा मंत्री की हैसियत से विराजमान हैं यहां बिहार के रहनुमा मुख्यमंत्री, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के जिसके अध्यक्ष वे रहा करते थे और अध्यक्ष के नाते मुझे भी रहने का अवसर मिला, मुझे विश्वास था कि शायद बिहार के रहनुमा, सामाजिक न्याय के मुख्यमंत्री शिक्षा से जुड़े मुख्यमंत्री, बिहार में शिक्षा क्षेत्र को लोकतांत्रिक अधिकार देंगे, किन्तु आज दुर्भाग्य है। मैं उन सभी विषयों को यदि समय मिला

तो कहने का प्रयास करूंगा, परन्तु सबसे पहले मैं प्राथमिक शिक्षा की ओर आपका ध्यानाकृष्ट करता हूं ।

महोदय, प्राथमिक शिक्षा जो दिखायी पड़ रही है पूरे बिहार में, प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति है ? कहीं जाइये, पेड़ के नीचे शिक्षक मिलेंगे, आप कहीं प्रवेश करेंगे, कई बार क्षेत्र से गुजरते हैं, देखते हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, शिक्षक खैनी खा रहे हैं और विद्यार्थी बना कर खिला रहे है। जो प्राथमिक शिक्षक को सम्मान मिलना चाहिये, उससे सरकार उदासीन है। सरकार पूरी तरहं से शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, जिसको खत्म करना चाहिये था उसको और बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे मालूम है कि शिक्षा के अन्दर मैं प्राथमिक शिक्षा की बात करता हूं, प्राथमिक विद्यालय लगभग 52 हजार हमारे बिहार के अन्दर हैं जिमसें मध्य विद्यालय हैं, कुल मिलाकर 65 हजार विद्यालय के अन्दर हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इन विद्यालयों में कितने भवनविहीन विद्यालय हैं ?

सभापति महोदय, आज लगभग 40 हजार ऐसे विद्यालय हैं भवन विहीन है या भवन है ही नहीं। महोदय, भागलपुर शहर की बात को छोड़ दीजिये, मैं पटना राजधानी की बात कर रहा हूं, यहां पर आपसे मात्र 200 गज आगे जो आर-ब्लॉक के अंदर एम० एल० ए० फ्लैट है, वहां पर जो विद्यालय चला करता था, तीन साल तक उस विद्यालय का स्थानान्तरण होता रहा। कभी एक एम० एल० ए० फ्लैट में गया तो कभी दूसरे एम० एल० ए० के छत पर विद्यालय टहलता रहा, विद्यार्थी भी नहीं है। महोदय, मात्र 200 गज यहां से दूरी है, आर-ब्लॉक एम० एल० ए० फ्लैट के अंदर आज भी वह विद्यालय जिंदा है। महोदय, मैं

चाहूंगा कि इस प्रकार के विद्यालय जो कागज पर विद्यालय हैं और हमारे शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हम शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ा रहे हैं, शिक्षा का आगे विकास कर रह हैं, शिक्षा के लिए इन्होंने 22 अरब रुपये का बजट दिया है, 18 अरब रुपये का पिछली बार दिया था, लगभग 4 अरब रुपया इस बार ज्यादा दिया है, लेकिन शिक्षा के अंदर जो भ्रष्टाचार है, लाल फीताशाही है, जिस प्रकार के कदाचार शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त है, हमें कहने में शर्म आ रही है, शिक्षा क्षेत्र के अंदर जो माफिया फल-फूल रहे हैं, उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सभापति महोदय, शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय के अंदर आज कोई शिक्षक, यह कहा जाता है कि ऊपर से यह निर्देश है कि विद्यालय नहीं जाओ और हाजरी बनवा लो, प्रखंड के प्रदाधिकारी से लेकर ऊपर तक के पदाधिकारी कि मिलीभगत से करोड़ों रुपये का प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों से सूद टैक्स के रूप में वसूला जा रहा है और वह टैक्स कहां जा रहा है महोदय ? दुर्भाग्य है इस राज्य का , शिक्षक संघ में ऐसे नेता भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, कभी डाक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी के समय में शिक्षा क्षेत्र के प्रति कांग्रेस के समय में जो उदसीनता बरती गयी, वही उदासीनता वही भ्रष्टाचार आज जनता दल की सरकार के समय में है।

सभापति : समय आपका हो रहा है और लोगों को भी बोलना है।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : सभापति महोदय, मुझे 15 मिनट बोलना है, अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

सभापति : डिमांड पर 15 मिनट बोलना है, यह आपको किसने कह दिया। अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री अश्विवी कुमार चौबे : महोदय, छात्र आंदोलन में सन् 74 में यह नारा दिया था कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, आज राज्य की नौनिहालों की क्या स्थिति है, शिक्षा के क्षेत्र में। जय प्रकाश आंदोलन से जुड़े बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री यहां मौजूद है, महोदय मैं चाहता हूं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो लेकिन ...

सभापति : आप अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : 15 मिनट मुझको बोलने का समय दिया जाये, अभी हम पांच मिनट ही बोले हैं।

सभापति : अभी आपको 5 मिनट ही बोलना है, किसने कह दिया कि डिमांड पर आपको 15 मिनट बोलना हैं

श्री अश्विनी कुमार चौबे : महोदय, 1982 से कॉलेजों के टीचर की नियुक्ति नहीं हो रही है, 1992 से नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक कॉलेजों में नियुक्ति नहीं हो पायी है।

श्री अश्विनी कुमार चौबे : पांच मिनट और बोलने दिया जाय।

सभापति : अब आपको समय नहीं दिया जायेगा, 4.30 में सरकार का जवाब शुरू होगा, हम क्या कर सकते हैं इसमें, समय ही कम है। माननीय सदस्य श्री अश्विनी कुमार चौबे जी

की बात अब नहीं लिखी जाय, माननीय सदस्य श्री अब्दुल गफूर आप अपना भाषण शुरू करें ।

श्री अब्दुल गफूर : सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के जरिये जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो साहसिक कदम शिक्षा के स्तर के लिए लाया है, इसके लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं । चूंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख रहा हूं । सभापति महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने एक साहसिक एवं क्रांतिकारी कदम उठाया है। आज उच्च विद्यालय में 20-25 वर्षो से एक ही विद्यालय में जो शिक्षक कार्य कर रहे थे और जो शिक्षा माफिया गरीबों का शोषण करके शिक्षा की जो बदनामी हो रही थी, उसको शिक्षा मंत्री ने हिम्मत से काम लेकर सुधार का काम किया है। समय पर परीक्षा लेकर उसका समय पर परीक्षाफल प्रकाशित करने का काम किया है, चाहे वह इंटर का परीक्षाफल हो, महाविद्यालय का परीक्षाफल हो या उच्च विद्याल का परीक्षाफल, हो माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देते हुए अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां कुछ ऐसे गांव है, 200 की आबादी पर जो एक उर्दू शिक्षक देने की बात है, महिषरी प्रखंड के कुम्हरा, एना, मंगरौनी, झाड़ा, पिपरपाती तथा नवहट्टा प्रखंड में कुम्हरौली, कासीमपुर, केदली, हारी, परताहा, झरब तथा महिषी प्रखंड में सपेताभरना,

प्राणपुर, सोरबा, समारी भरना आदि गांवों में अब तक विद्यालय नहीं खुले है। महोदय, इन गांवों में विद्यालय खुलना चाहिए इनके अतिरिक्त बिहार में जो 52 मदरसा है, जिसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार के 52 मदरसे, जिसकी 1993 में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृति मिली और जनवरी 95 में शिक्षा मंत्री ने भी आदेश दे दिया कि इन 52 मदरसों में जो शिक्षक कार्यरत हैं, उनके वेतन का भुगतान किया जाय, लेकिन शिक्षा विभाग के सचिव श्री के० डी० सिन्हा की उदसीनता के कारण, उनके लापरवाही के कारण और मनमानी के कारण आज तक उन 52 मदरसों में कार्यरत करीब 350 शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो सका है। बार-बार आश्वासन देने के बाद भी विभाग में आज तक वह फाइल पड़ी हुई है, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए।

सभापति : आपका समय समाप्त हुआ। माननीय सदस्य श्री फुरकान अंसारी जी आप अपना भाषण शुरू कीजिये।

श्री फुरकान अंसारी : सभापति महोदय, मेरे बदले माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव जी बोलेंगे ।

सभापति : ठीक है। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव जी आप बोलिये।

श्री मनोज कुमार यादव : सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग का जो बजट प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, शिक्षा विकास

का पर्याय अंग है, जिस तरह से दूध से सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी तरह से शिक्षा को विकास से पृथक नहीं किया जा सकता है। महोदय, अभी जो हमने शिक्षा प्रस्ताव के बुकलेट को देखा है, उसमें पांच नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के बारे में है, लेकिन मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो पांच नये विश्वविद्यालय बने हैं, वे इक्यूप्ड नहीं है, कहीं भवन नहीं है, कहीं जमीन नहीं है, कहीं इक्यूड नहीं है । कहीं भवन नहीं है। कहीं जमीन है । कहीं लेबोरेटरी नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जहां नये विश्वविद्यालय खुले हैं, उन्हें वेल इक्यूप्ड किया जाय ।

जब माननीय मंत्री जी पिछले साल अपना बजट भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि हम इन पांच विश्वविद्यालयों के अलावे माइनोरिटी के लिए मौलाना मजरूल हक विश्वविद्यालय पटना में स्थापित करेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस वर्ष भी नहीं हो पायेगी, जिससे प्रतीत होता है कि माइनरिटी की शिक्षा के लिए माननीय मंत्री जी के मन में कोई दिलचस्पी नहीं है। महोदय, यह सामाजिक न्याय की सरकार है और जिस सामाजिक न्याय की सरकार से जिन श्रेणी के लोगों को अपेक्षा होनी चाहिए, वैसे लोगों के लिए आज प्राथमिक विद्यालयों की हालत जिलों में बहुत ही खराब है। अपेक्षाकृत पूरे बिहार की, खासकर हमारे जिले में जितने प्राथमिक विद्यालय हैं, जितनी उनकी संख्या होनी चाहिए, उतनी नहीं है, यदि प्राथमिक विद्यालय हैं भी तो पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं

है, यूनिट सेक्सन नहीं है और शिक्षकों की बहुत कमी है। महोदय, शिक्षकों में बहुत कदाचार है, वे समय पर स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है, तो फिर सामाजिक न्याय में आने वाले लोग कैसे सामजिक न्याय पा सकेंगे । सभापति महोदय, प्राथमिक शिक्षा समिति की बैठक की जाती है, लेकिन हमारे हजारीबाग जिले में बैठक नहीं होती है। कुछ स्कूलों को मिडिल स्कूलों में उत्क्रमित किया गया है, लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो पाया है। बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रखंड में एक प्राजेक्ट स्कूल का निर्माण कराया जायेगा; लेकिन हजारीबाग जिले के पदमा प्रखंड में प्रोजेक्ट स्कूल का निर्माण नहीं हो रहा है।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

महोदय, ऐसे ढेर सारे प्रखंड छोटानागपुर में है, जहां प्रोजेक्ट विद्यालय नहीं है जिस प्रखंड में प्रोजेक्ट स्कूल नहीं है और हमारे यहां हजारीबाग जिला में मदरसा के जो शिक्षक हैं उनको 6-6 महीना से पेमेंट नहीं हुआ है और इस तरह के माईन्योरिटी स्कूल में, हाई-स्कूल हैं वहां के शिक्षकों का 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना से भुगतान नहीं हो पा रहा है।

माईन्योरिटी स्कूल के शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है और जैसा कि बजट में बात कही गई है कि प्रत्येक प्रखंड में चार हाई स्कूल होंगे आंबादी के अनुसार, लेकिन हाई स्कूल बनाने के लिये कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। एक और माननीय सदस्य बचे हुये है।

श्री मनोज कुमार यादव : अध्श्यक्ष महोदय, मैं यह बतलाना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री ने अपने बजट प्रस्ताव में बतलाया है कि शिक्षा योजना मद में जो राशि आवंटित की गई है उसे पर्याप्त कहा जा सकता है, लेकिन जो विकास योजना की राशि आवंटित की गई है, वह बहुत ही अपर्याप्त है, इससे ऐसा महसूस होता है कि शिक्षा के प्रति जो अखबार में आप बयान देते हैं, अपने आप को शिक्षा के प्रति रूचि दिखलाते हैं, शिक्षा के प्रति आज बहुत सजग हैं, लेकिन सच पूछा जाये तो शिक्षा की तरक्की के लिये आप सजग नहीं है।

श्री रामानाथ यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग पर वाद-विवाद चल रहा है। शिक्षा विभाग में मैट्रिक का जो रिजल्ट हुआ, आई० ए०, बी० ए० का जो रिजल्ट निकला उसमें शिक्षा विभाग का जो रूप था वह सामने आ गया, सामने लोगों को दिखला दिया। इसका पूरा पोल खुल गया कि क्या शिक्षा विभाग है। इतना तक गड़बड़ी हुई है कि रिजल्ट निकालने में न जाने कितना प्रतिशत इन-कम्पलिट है, कम्पलिट है -इससे इतना झंझट पैदा हो गया कि स्थिति और दयनीय होती चली जा रही हैं दिन भर बोर्ड ऑफिस के आगे-पीछे, उसके गार्जियन और विद्यार्थी चक्कर काटते हैं कि हमारा परीक्षाफल में सुधार कैसे हो सकता है और वहां काफी चढ़ावा देना होगा। समस्या इतना ही नहीं है - सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने जिन

स्कूलों की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की थी । पहली जिस विद्यालय से पीरक्षा देने का आदेश था, उसमें सरकार ने अब कहा कि इन विद्यालयों को राजकीयकृत विद्यालय से टैग कर दिया गया था, इस बार सुनने में आया है कि किसी के साथ टैग नहीं हुआ है, लेकिन जो विद्यार्थी स्थापना स्वीकृत विद्यालय जो हैं उसमें पढ़ रहे हैं उसके बारे में शिक्षा विभाग, उसके कमीश्नर और जो उनके डायरेक्ट हैं या डी० ई० ओ० हैं । वे इस संबंध में बहुत कुछ सोचते नहीं है ऐसे स्कूल जिसे सरकार ने स्वीकृति दे दी । मैं चाहूंगा कि सरकार जब अपना वक्तव्य दे तो यह बतायें कि ऐसे विद्यालय के विद्यार्थियों का भविष्य क्या है ? कैसे इम्तिहान कैसे देंगे इस बारे में बतायें। एक कहावत है 'लड़का मालिक बूढ़ा-दीवान, मामला बिगड़े सांझ विहान ।' शिक्षा विभाग में भी यही बात हो रही है ? इस विभाग के कमीशन वाले नहीं है, कोई माननीय सदस्य यह नहीं कहा सकता है कि विधायक जाकर बात कर सकता है-डायरेक्टर भी सुनने को तैयार नहीं है।

श्री राजो सिंह : कौन पटना के कमीश्नर सुनने वाले नहीं है ?

श्री रामनाथ यादव : जी नहीं, शिक्षा विभाग के कमीश्नर सुनने वाले नहीं है। जब कभी मैं गया आपके सचिवालय में, डायरेक्टर से भेंट करने के लिये गया था कमिश्नर भेंट करने के लिये गया तो मालूम हुआ वे चले गये हैं, हाई-कोर्ट हर बार कहा जाता है चले गये है। हाई-कोर्ट दिन भर हाईकोट . हो

रहते हैं तो इसी से अंदाज कर लीजिये कि शिक्षा विभाग का काम कितना गड़बड़ चलता है। इतनी गड़बड़ी इन लोगों ने पैदा किया है कि अधिकांश शिक्षक को हाईकोर्ट की शरण में हमेशा जाना पड़ता है। मदरसा बोर्ड और मदरसा स्कूल की हालत भी काफी दयनीय बना दिये हैं, ये लोग कभी भी कोई शिक्षक की बात सुनने को तैयार नहीं, विधायकों की बात को सुनने को तैयार नहीं है और अपने मनमाने ढंग से काम करने को तैयार है। क्या शिक्षा विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है ? आज सुबह से इस सदन में देख रहे हैं कि जब से इस विभाग के बजट पर बहस शुरू हुई है जितने स्कूल हैं, सारा स्कूल जर्जर है, प्राईमरी स्कूल की हालत खराब है, मिडिल सकूल की हालत खराब है, हाई-स्कूल के टीचर्स की बदली के कारण, ये गड़बड़ी पैदा हो गई है। एक स्कूल में एक ही सबजेक्ट के तीन-तीन, चार-चार शिक्षक हैं और किसी विषय में एक भी नहीं है, यदि यह झूठ बात हो तो मैं कोई भी सजा भोगने के लिये तैयार हूं। कहीं यूनिट से ज्यादा टीचर्स हैं तो कहीं यूनिट से कम टीचर्स हैं, इस तरह कैसे पढ़ाई हो सकती है और आप कहते हैं कि शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। इस तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं, इस तरह की जो गड़बड़ी है - शिक्षा मंत्री को मालूम हो या नहीं बदली में काफी रकम चल रही है, भले शिक्षा मंत्री को मालूम हो या नहीं किन्तु बदली में इस सरकार को इतना बदनाम किया जा रहा है, ये तमाम पदाधिकारी शिक्षा विभाग को बदनाम कर रहे हैं, श्री लालू प्रसाद का नाम मिटाने पर पड़े हुये हैं और शिक्षा मंत्री का नाम भी मिटाने पर

पड़े हुये हैं। शिक्षा मंत्री कभी बैठक भी नहीं बुलाते हैं और कभी राय भी नहीं लेते है कि क्या हो रहा है। आपके कमीश्नर बतलाये कि कम से कम कितने विद्यालयों में हेडमास्टर नहीं है, आपके विद्यालय लावारिश की तरह चल रहे हैं और आप शिक्षा में इसी तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं ? हम चाहते हैं कि हाई स्कूल में हेड मास्टर हो, मिडिल सकूल में हेडमास्टर हो और विद्यालय को जो भवने हैं प्राईमरी स्कूल से ही ले लीजिये, प्राजेक्ट स्कूल को ले लीजिये, इनकी अवस्था ठीक हो। हमारे निर्वाचन क्षेत्र विम में एक नवोदय विद्यालय है, उस नवोदय विद्यालय में छात्रों का नामांकन बंद हो गया है कारण उसके पास जमीन नहीं है, करोड़ों रुपया भारत सरकार ने इसके बिल्डिंग बनाने को दी है, सरकार आज तक उसे जमीन उपलब्ध नहीं करायी है-चरवाहा विद्यालय के लिये 27 एकड़ जमीन जो कृषि विभाग से मिली है, यदि उस जमीन को नवोदय विद्यालय को दे दी जाय तो नवोदय विद्यालय का बिल्डिंग बन जाय।

अंत में मैं दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय कि स्थापना स्वीकृत विद्यालय के विद्यार्थियों की पढ़ाई की व्यवस्था और इम्तिहान कैसे होगी इस पर चाहेंगे कि माननीय मंत्री जब सरकार की ओर से जवाब देंगे, इस संबंध में भी बतायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । सरकार का जवाब ।

श्री राजो सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन पर चला गया, मुझे टाईम नहीं मिल सका । मैं शिक्षा पर बोलना

चाहता हूं, मैं इसको 3-4 मिनट का समय चाहता हूं मैं आपसे और मंत्री जी, दोनों से रिक्वेस्ट है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बजट पर आज अवसर मिला है मैं अपनी बातों को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उस व्यक्ति में नहीं हूं जो गलत सदन में आंकड़ा और बात को उपस्थित करूं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी अकेले कुछ नहीं है, इनका इतना लम्बा-चौड़ा विभाग है- हाथ है, नाक है कान है जो अधिकार जो काम करते है वे इनके आंख-कान है। शिक्षा विभाग में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको अवसर नहीं मिला है और हमारे माननीय मंत्री महोदय, किसी को अवसर नहीं मिला होगा, लेकिन जनता दल के भी जो माननीय सदस्य मेरे जैसे हैं उनको भी यह अवसर मिला होगा कि शिक्षा विभाग के जो कमिश्नर है अगर उनको टेलीफोन कीजिये तो उनका प्राईवेट सेक्रेटरी कहता है कि वे बहुत बिजी हैं। मुझे एक मिनट बोलने दीजिये। सेकेन्ड्री के जो डी० पी० आई० हैं उनको अगर आप पत्र लिख दीजिये कि इस मास्टर के साथ अन्याय हुआ है, आपने फैसला ले लिया है कि हम टीचर्स का ट्रांसफर कर देंगे और अपने टीचर्स का ट्रांसफर कर दिया-हमलोगों को कोई एतराज नहीं है, जिसको जहां भेजना था भेजा ? एक-एक सब्जेक्ट का तीन टीचर भेज दिया-अगर हमने किसी टीचर्स को पत्र लिखकर भेज दिया या शिक्षक गये हैं तो दण्डित हो गये और उनकी परेशानी हो जायेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जन-प्रतिनिधि लोग है, एम० एल० ए०, एम० पी० है, यह हमें सुविधा और विशेषाधिकार प्राप्त है कोई आदमी पूछ नहीं सकता है-किसी डिपार्टमेंट को पत्र लिखते हैं कि फलां आदमी कष्ट में है तो इनकी सेक्रेसी हम से कोई नहीं पूछ सकता है, यह हमको प्रोटेक्शन है।

हमने आपको पत्र लिखा और जो टीचर उस पत्र को लेकर गया, उसे दंडित किया गया लेकिन जिसको दंडित किया गया, मैंने उसको नौ हजार रुपया दिया क्योंकि वह गरीब आदमी था। हमने कहा तुम नौ हजार रुपया ले लो और वह आदमी आर० डी० डी०, भागलपुर से वैकडेंट में ऑर्डर लेकर चला आया। अकेले शिक्षा मंत्री क्या कर सकते हैं। इनके डी० पी० आई० मिलते नहीं है। क्या आपका हाथ इतना कमजोर था कि विभाग की राय पर सारे शिक्षकों को बदल दिया। मंत्री महोदय, बदली कर दिया ठीक है, लेकिन इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सचिवालय में हेडमास्टर, सहायक हेडमास्टर बैठे हुए हैं और आप उनको नहीं बदल सकते हैं, इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। आप सहायक टीचर, हेडमास्टर, प्राईमरी स्कूल के टीचर को बदल दीजिए इससे कल्याण होनेवाला नहीं है। हमारा कल्याण होनेवाला है उनसे जो ऊपर में बैठे हुए हैं और वे इमानदार है या नहीं, वे न्याय कर रहे हैं या नहीं, वे माननीय विधायकों को इज्जत कर रहे हैं या नहीं । आप मंत्री है। आपकी बात सुन लेते होंगे लेकिन जब मंत्री पद से हट जाइयेगा तो आपका भी वही हालत होगा जो अन्य विधायकों का होता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। आपलोगों ने भाषण दिया। अब सरकार का जवाब भी तो सुनिये।

श्री रामबली सिंह : अध्यक्ष महोदय, हर दल को आपने समय दिया और हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये। आप बैठिये न । इनको जवाब देने दीजिए। माननीय सदस्य बैठ जाये।

श्री जय प्रकाश नारायण : अध्यक्ष महोदय, 17 माननीय सदस्यों ने शिक्षा विभाग की मांग पर अपनी राय व्यक्त करने का काम किया है और शिक्षा जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, की चर्चा को गंभीरता से नहीं ले और सदन में गंभीरता से चर्चा नहीं करें और आपा धापी होता रहे तो बाहर अच्छी ईमेज नहीं बन पायेगी ।

मैं सभी माननीय सदस्यों का शुक्रगुजार हूं, कि आपकी बेहतर राय आयी और आपकी राय कहीं-न-कहीं एक अच्छे नतीजे पर पहुंचायेगा ।

धीरे-धीरे सरकार का पक्ष सुनने का काम करेगी जिससे मेरा उत्साह बढ़गा। आज बिहार में ऐसी ताकतें शिक्षा के क्षेत्र में मकरजाल बनाकर बिहार के शैक्षणिक विद्यालयों में प्रदूषण फैलाने का काम किया है। जहां 2,5,10 और 15 साल में नहीं वर्षो-वर्षो से शिक्षा में जो भयंकर मकरजाल था, उस जाल को तोड़कर साफ करने का काम किया है। आज जो शिक्षा बिहार में है, शिक्षा जहां हैं, उसे आगे ले जाना चाहते है। जिन माननीय

सदस्यों ने राय दी, उनको एक-एक कर जवाब दे देंगे । कहीं ऐसी बात आयी है जिसको सुधारने की जरूरत है, कहीं ऐसी बात है जहां भूल हो गयी हो उसकी सूचना दे देंगे कि रियलिटी यह है । लेकिन शिक्षा जगत में आज हम जहां खड़े हैं और जो माहौल है, उससे आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ने में कहीं-कहीं कठिनाई होगी। इसके लिए आपका समर्थन चाहते हैं।

माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने सत्ता में आने के बाद यह घोषणा की थी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रदूषण है, माफियागिरी है, जो बर्बाद कर रहा है, ऐसी ताकतों को जो बिहार में पनप रहे हैं, फल-फूल रहे हैं उनको पनपने नहीं देंगे और उनको तोड़ने का काम करेंगे। यह संकल्प है। शिक्षा के क्षेत्र में जहां हम आज खड़े हैं, उससे आगे बढ़ना चाहते है। इसके लिए आपका समर्थन चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं ।

आज बहस के दौरान मैनेजिंग कमिटी की चर्चा की गयी। यह उनका संवैधानिक दायित्व है। हम इसका विरोध नहीं करेंगे। इस संबंध में जो परिपत्र है, वह मेरे सामने है। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है- "बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण" अधिनियम, 1981 की धारा 6 एवं संशोधित अधिनियम, 1993 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य के प्रत्येक राजकीयकृत उच्च विद्यालयों के लिए निम्नांकित रूप से प्रबंध समिति का गठन किया जाता है-इसमें है कि जिस विधान सभा क्षेत्र में विद्यालय अवस्थित है उस क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करने वाले बिहार विधान सभा के माननीय

सदस्य उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। यदि उस क्षेत्र के माननीय सदस्य राज्य सरकार में मंत्री हों तो वे अपना प्रतिनिधि मनोनीत कर सकते है। यह परिपत्र मेरे सामने है। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि मैनेजिंग कमिटी की बैठक नहीं होती है। हम कल ही इस संबंध में सभी जिलों के डी० एम०, डी० डी० सी० को निर्देश देंगे कि जल्द से जल्दी इसकी बैठक आयोजित करें लेकिन आज जो गड़बड़ियां है उसको एक मैनेजिंग कमिटी बना कर, माननीय सदस्य राजो बाबू बैठे हुए हैं, वो जानते हैं। कमिटी हम बनाये हैं, इसमें कई माननीय सदस्य होंगे, सैकड़ों होंगे । कमिटी बना कर दस दिन के बाद हाई स्कूल में भी देखने की बात है लेकिन अभी हमारा दायित्व है कि यह मैनेजिंग कमिटी बनाईए, इसके लिए वर्षो से घोषणा नहीं हुई थी लेकिन हमने उसको अमली जामा पहना कर हाई स्कूल में भी मैनेजिंग कमिटी देने का काम किया है। यदि वह गलत हुआ है तो अब हमें कुछ नहीं कहना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिए, मंत्री जी को बोलने दीजिए ।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, यह कमिटी माननीय सदस्य से ही बनी है, आप ही इसके अध्यक्ष है। मैं यह परिपत्र फिर दे दूंगा। मैंने फिर कहा है कि हमारे पहले जिलों में प्लानिंग कमिटी नहीं थी, कहीं भी प्लानिंग कमिटी नहीं थी। हमने इम्मेडिएट प्लानिंग कमिटी बनाने का काम किया है जिसके डिस्ट्रीक्ट मजिस्ट्रेट अध्यक्ष हैं और माननीय सदस्यगण इसके सम्मानित मेम्बर है और जहां भी स्कूल की

कमी है, सामंजन करके विद्यालय खोला है। गरीब लोगों, हरिजन-आदिवासी, पिछड़े लोगों और अल्पसंख्यक लोग जो हैं। उनके लिए विद्यालय की स्थापना की व्यवस्था, यूनिट की व्यवस्था प्लानिंग कमिटी की बैठक कर, जिसकी घोषणा कर दी गयी है, माननीय सदस्यों की बैठक आयोजित की गई है और जहां नहीं की गयी है इसके लिए भी कल निर्देश दे देंगे और डी० एम० को कि जल्द-से-जल्द, सत्र के बाद प्लानिंग कमिटी की बैठक बुला कर माननीय सदस्यों को, जो जिस क्षेत्र के हैं उनको बुलायें कई ऐसे सवाल हैं, मैं उस सवाल को उठाना चाहता हूं। साक्षरता अभियान के संबंध में पूरे के पूरे बिहार में जो माहौल रहा है उसमें निश्चित रूप से बेहतर काम हुआ है। पहले की तुलना में अब अधिक साक्षर लोग हैं।

आज बिहार अगड़ाई लेना चाहता है, बिहार खड़ा होना चाहता है, हम पैसे का बंदरबांट नहीं करना चाहते है। आज हमने विद्यालय चलो अभियान चलाया है, विद्यालय चलो अभियान 8 सितम्ब्र से हमने चलाया है। किशनगंज जैसा इलाका जो मुसलमान भाई का इलाका है वहां के भाईयों, बहनों, छात्र छात्राओं की बैठक की गई और समझाया कि विद्यालय अभियान में चलो। विद्यालय चलो अभियान का नारा दीवाल में लिखा हुआ है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां दीवाल में नहीं लिखा हुआ है। विद्यालय चलो अभियान के तहत छात्रों को स्कूल जाना है, पढ़ाई-लिखाई कराना है। पढ़ो या मरो का नारा आज हमने इस अभियान में चलाया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ 2 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक, बिहार में स्पेशल एडमिशन

का ड्राईभ प्राईमरी स्कूलों के लिए चलाया गया और खुशी की बात है कि हमने 7 लाख बच्चे, बच्चियों का एडमिशन प्राईमरी स्कूलों में कराने के लिए निकले, कमीश्नर निकले, अधिकारी निकले, डी० एम० और डी० डी० सी० भी निकले। आप माननीय सदस्य भी निकले होंगे । उसके बाद यह खुशी की बात है कि बिहार के छात्रों के लिए गौरव की बात है कि प्राईमरी एडुकेशन में जो स्पेशल ड्राईभ नामांकन का चलाया है उसमें 7 लाख की जगह 16 लाख लड़के लड़कियों का एडमिशन इसी बिहार में 2 जनवरी से 28 फरवरी तक किया गया। धनबाद में एक दिन में 40 हजार एडमिशन हुआ। वहां के डी० एम०, डी० डी० सी०, सभी शिक्षक छात्र और जो स्वयं सेवी संस्थाएं है वे सभी निकले थे। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मेरा काम आपको उज्जवल नहीं लग रहा हो लेकिन निश्चित तौर से सरकार की मंशा को देखनी चाहिए, सरकार के सोच को देखना चाहिए कि किन-किन क्षेत्रों में अच्छा-अच्छा काम किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी के वक्त कहा था कि 'डु एण्ड डाई' । बिहार के मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद ने बिहार की निरक्षता को समाप्त करने के लिए, मिटाने के लिए पढ़ो या मरो का नारा दिया। हमको पढ़ना है या मरा हुआ समझना है। आज यह नारा गांव-गांव में पहुंच गया है। यह नारा किसी दूसरे राज्यों में नहीं दिया गया है। 'जन्म दिया है तो शिक्षा दो' इस नारा को फैलाया गया है। आजादी के वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' आज कोई अंग्रेज नहीं है। हम अपने देश में हैं, अपने वतन में है, अपने मिट्टी में है। आज

हमारा नारा है कि 'निरक्षरता बिहार छोड़ो' इसके लिए हम सब भारतीयों को आगे आना चाहिए । आजादी के वक्त महात्मा गांधी ने कहा था कि 'एक पाई, एक भाई' दीजिए। सदन के माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, विनती करना चाहता हूं कि बिहारवासियों की साक्षरता सिर्फ सरकार का पक्ष नहीं है, आपका भी पक्ष है बिहारवासियों के तमाम बुद्धिजीवियों, प्रोफेसर, लेक्चरर, इंजीनियर जो पढ़े लोग है इसमें सभी का हिस्सेदारी, भागेदारी होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के वक्त में कि एक पाई और एक भाई चाहिए। आज मैं एक पाई मांगता हूं लेकिन घर-घर में एक भाई चाहिए जिससे निरक्षता के कलंक को मिटाया जा सके। बिहार को साक्षर बनाने के लिए सबको आगे आना चाहिए वरना बिहार साक्षर नहीं बन सकता है। नया बिहार किस तरह से बनाना है वह हम सभी जानते हैं जहां गड़बड़िया हैं उसको हम जानते हैं। उससे हम मुकरना नहीं चाहते हैं । हम कहे, आप माननीय सदस्य बोलते हैं, हम उसका स्वागत करते है। आप कहते हैं कि नीचे में गड़बड़ी है। आप बोलते हैं तो हमारा छाती गदगद हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि जहां शिक्षा के क्षेत्र में नीचे में जो दाग लगता है, पदाधिकारी हों या नीचे में जो माफिया का जाल फैलाये हैं जो लगातार इस बिहार को लूटते रहे है। उस पर हम कार्रवाई करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, साक्षरता का जो अभियान चलाये हैं उसका जवाब सदन में देंगे, उसको सुनना चाहिए। दूसरी बात क्या

बोलेंगे ? मैं चाहता हूं कि जैसे सूरज की रोशनी बिना किसी भेदभाव पूर्ण सबों को मिल जाता है महलों में रहने वालों को, तंग बस्तियों में रहने वालों को उसी तरह चन्द्रमा की शीतल बिना किसी भेदभावपूर्ण के सबों को मिल जाती है। हिन्दुस्तान में आजादी के बाद जो हमारा संविधान बना कि 6-15 वर्ष के बच्चों को साक्षर बनायेंगे, प्राईमरी एजुकेशन देंगे तो हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया।

आजादी के 50 साल बीतने के बाद आज देश में, बिहार में 6-14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नहीं दे सके । साक्षर नहीं किये है। हम चाहते हैं कि जैसे सूर्य को रोशनी और चन्द्रमा को शिथिलता बिना भेदभाव के सबों को मिलती है उसी तरह से ज्ञान की रोशनी को भी हम बिना किसी भेदभाव के सबों तक पहुंचाना चाहते हैं । हम अंतिम स्वर तक गरीब गुरूबा तक इसको पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा करने से नया बिहार बनेगा । अगर नया बिहार बनाने का दम है तो वह जनता दल की सरकार में है और निश्चित तौर पर उसी दिशा में जय प्रकाश नारायण यादव भी काम करना चाहता है। हमने कहा था अध्यक्ष महोदय, कि शिक्षा विभाग को चुस्त और दुरूस्त करने के लिये चट्टान भले ही पिघल जाये लेकिन जय प्रकाश नारायण यादव का इमान नहीं पीघलेगा। हमारे विभाग में जो ी गलत काम करेगा वह निश्चित तौर पर दंड का भागी होगा। निश्तिच तौर पर ऐसे लोग जो नीचे में पैसा लेकर काम करते हैं उसको हमारी सरकार और हमारे जैसे लोग बर्दास्त नहीं करेंगे। लेकिन जिन बातों की चर्चा कर रहे है। उनमें पेट की भूख भी है और दिमाग की गुलामी भी है। डा० लोहिया कहा

करते थे कि पेट की भूख को 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा भी सहने कीं जरूरत हो तो गरीबों तुम उसे सह लेना लेकिन कोई दिमाग से तुम्हें एक मिनट भी गुलाम बनाना चाहेगा तो उसे कभी बदास्त नहीं करना। तभी नया बिहार बनेगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। हम किसी की गुलामी बर्दास्त नहीं करेंगे । आज हम शिक्षा जगत में एक नया वातावरण बनाने का काम किया है।

आज इसे सुधारना है, नये सिरे से आगे ले जाना है। जो प्राईमरी शिक्षा है, जो शिक्षा का आधार है, जो शिक्षा की बुनियाद है जब तक वह ऊंचा नहीं उठेगा, प्राइमरी शिक्षा ही हमारी इमारत है। उसी पर छात्र का भविष्य निर्भर करता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, समय नहीं है, हम प्वायंट वाइज कहना चाहते थे लेकिन समयाभाव के कारण वैसा नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा भवन विहीन विद्यालय है, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य करते है। भवन विहीन विद्यालय नहीं रहने देंगे । हमने कहा कि दो साल के अंदर बिहार में एक भी प्राइमरी विद्यालय भवन विहीन नहीं रहेगा । उसको पक्का मकान में बदला जायेगा। अध्यक्ष महोदय, राजबाला वर्मा यहां की डी० एम० हैं जब वह मुजफ्फरपुर में थी तो उसने पाया कि मुजफ्फरपुर में 2000 प्राइमरी शिक्षक डेप्यूटेशन कराकर वहां बैठे हुए थे। प्राइमरी एजुकेशन में कहां से यह उद्योग चल रहा था। हमने तुरंत उसको तोड़ने का काम किया है। सभी फालतू शिक्षकों को वहां से हटा दिया । मुजफ्फरपुर के सारे

मकरजाल को हमने तोड़ दिया। प्राइमरी विद्यालय में जहां दो शिक्षक रहना चाहिए वहां चार-चार शिक्षक हो गये और कहीं-कहीं 10-10 हो गये थे उसको तोड़ा गया है। बिहार के 25 हजार शिक्षकों की बहाली की गई है । हरिजन, आदिवासियों का जो 15 साल का बैकलॉग था, उसके लिये विज्ञापन निकाला गया है। शिक्षकों की बहाली करेंगे । लोक सेवा आयोग को शिक्षकों की बहाली के लिये परीक्षा लेने को कहा गया है। उसके लिये विज्ञापन निकला है। लोग फार्म भर रहे है। यह सरकार की उपलब्धि है।

श्री राजकुमार राय अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं। माननीय सदस्य राजो बाबू ने सदन में चार्ज लगाया उस पर क्या हो रहा है। मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें । उस भ्रष्ट आदमी को अविलंब हटावें ।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : जिस आदमी पर माननीय राजो बाबू ने चार्ज लगाया है उस आदमी को छः दिन पहले मुख्यालय में बुला लिया गया है और उस पर अलग से कार्रवाई करेंगे । जैसे ही सूचना मिली उसे मुख्यालय में बुला लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, साक्षरता कमिटी के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जिला में साक्षरता कमिटी है उसम विधान मडल के सदस्य रहेंगे । इसके साथ-साथ 42 उर्दू शिक्षकों की बहाली की गई है। दोपहर का भोजन चालू किया जा रहा है। जो हमारे बुनियादी विद्यालय है उसके रख-रखाव में कुछ गडबड़ी है । मैं चाहूंगा कि उसका सामंजन करूं । उसका कैसे सामंजन करूं इस पर विचार कर रहे हैं। बिहार में परीक्षा का एक माहौल बना

है। आज समय पर परीक्षा हो रही है और समय पर रिजल्ट निकल रहा है। हम परीक्षा के लिये कैलेंडर निकालेंगे । चाहे जितनी भी दिक्कत हो, जितनी भी परेशानी हो हम बिहार के छात्र के प्रति चिंतित हैं। बिहार के शिक्षा के प्रति चिंतित हैं । हम बिहार में शिक्षा माफिया को चलने नहीं देंगे आज हमारे प्रदेश में शिक्षा का एक अच्छा माहौल बना है। आज हमारे लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिये जा रहे है। आज क्वांटिटी में भले ही कमी हुई है लेकिन क्वालिटी काफी बड़ी है। यह हमारे लिये शुभ संकेत है। हमारे यहां जितने भी शिक्षक हैं, प्रिंसिपिल है, महाविद्यालय से लेकर प्राथमिक विद्यालय और सेकेण्डरी विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं उनको पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा, हम इसमें कड़ाई करेंगे । निश्चित तौर पर हम इस काम को करेंगे । मैट्रिक की परीक्षा 14 फरवरी से शुरू होगी, फरवरी महीने में शुरू होगा। इंटरमीडियेट की परीक्षा भी फरवरी में शुरू होगी। हमने तय किया है निश्चित तौर से चाहे इंटरमीडियेट हो, मैट्रिक हो जो वातावरण बदल गया है उसको हम कायम रखेंगे । इस बात से हम हटने वाले नहीं है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के वातावरण में काफी सुधार हुआ है और आगे भी हम निरंतर सुधार का काम करते रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें ।

श्री त्रिवेणी तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा विभाग से माफिया को हटा रहे हैं तो

कम-से-कम वे ये घोषणा कर दें कि यहां से जाने के बाद सचिवालय में शिक्षा विभाग में जो माफिया है उनको हटा देंगे।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार जी अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री प्रेम कुमार : अयक्ष महोदय, आज शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, माफिया का राज चल रहा है, छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है, 200 करोड़ रुपया विश्वविद्यालयों का बकाया है, संस्कृत शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, उर्दू शिक्षकों का वेतन बकाया है, सीनेट की बैठक नहीं हो रही है। एक रुपया जो हरिजन बच्चों को जो प्रतिदिन देने की घोषणा की गयी थी वह नहीं दिया जा रहा है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

'इस शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटायी जाय।'

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं।

प्रश्न यह है कि -

'शिक्षा, खेल और युवा सेवायें तथा कला और संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 22,89,31,75,250 (बाईस अरब, नवासी करोड़, ईकतीस लाख, पचहत्तर हजार, दो सौ पचास) रु० से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई।